



नरेंद्र मोदी फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, 2014 से ही हैं शीर्ष पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता साबित हुए हैं। अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की 2024 की पहली तिमाही के लिए वर्ल्ड लीडर अप्रूवल रेटिंग रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 78 फीसदी लोग पीएम मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं और नरेंद्र मोदी को अपने नेता के तौर पर स्वीकृति देते हैं। इससे पहले दिसंबर 2023 की रिपोर्ट में भी पीएम मोदी 76 फीसदी अप्रूवल के साथ दुनिया में शीर्ष पर थे।

नई दिल्ली। इस बार 2 फीसदी ज्यादा लोगों ने पीएम मोदी के कामकाज पर संतुष्टि जताते हुए उन्हें अपने नेता के तौर पर मंजूरी दी है। इस सूची में पीएम मोदी के बाद 65 फीसदी अप्रूवल के साथ मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर दूसरे स्थान पर हैं। 63 फीसदी के साथ अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिली को तीसरा स्थान मिला है। चौथे स्थान पर 52 फीसदी के साथ पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क हैं। पांचवें स्थान पर स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति वियोला वैट्टीशिया एम्हर्ड को 51 फीसदी अप्रूवल रेटिंग मिली है।



2014 से ही शीर्ष पर, 93 फीसदी तक लोगों का समर्थन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं के कामकाज और उन देशों में नेताओं की लोकप्रियता को लेकर किए जाने वाले सर्वेक्षणों में 2014 से ही शीर्ष पर रहे हैं। सबसे पहले 2014 में प्यू रिसर्च ने पीएम बनने के कुछ माह बाद ही मोदी के कामकाज और नेता के रूप में देश में उनकी स्वीकार्यता को लेकर सर्वेक्षण किया, जिसमें 78 फीसदी लोगों ने पीएम मोदी का समर्थन किया। इसके बाद साल-दर-साल पीएम मोदी अलग-अलग रेटिंग एजेंसियों के सर्वेक्षणों में शीर्ष पर रहे। कोविड के बाद मई 2022 में लोकल सर्वेक्ल के एक सर्वेक्षण में पीएम मोदी को 67वें समर्थन मिला, जो उनका अब तक सबसे कम रेटिंग स्कोर है। जबकि, अप्रैल 2020 में आईएनएस-सीबीटी के एक सर्वेक्षण में 93वें लोगों ने उनका समर्थन किया जो उनका सर्वोच्च स्कोर है।

आलोचना छोड़े पश्चिमी मीडिया : एरिक सोल्हिम

पश्चिमी मीडिया में पीएम मोदी की छवि को नकारात्मक रूप से पेश किए जाने पर लगाइ लगाते हुए नॉर्वे के पूर्व मंत्री एरिक सोल्हिम ने कहा कि नरेंद्र मोदी से पश्चिमी मीडिया भले ही कितनी भी ईर्ष्या करता हो लेकिन 78 फीसदी की अनुलनीय अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता साबित हुए हैं। यही समय है कि पश्चिमी मीडिया को भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सकारात्मक कवरेज शुरू करना चाहिए।

सिर्फ 4 अन्य को 50त से ज्यादा रेटिंग

मोदी के अलावा सिर्फ चार नेताओं को 50वें से ज्यादा अप्रूवल रेटिंग मिली है। 30 जनवरी से 5 फरवरी के बीच किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर जारी रेटिंग में दुनिया के सबसे अमीर देशों के समूह जी-7 में शामिल अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और फ्रांस के नेताओं में से भी किसी को 50 फीसदी अप्रूवल रेटिंग नहीं मिली है। जी-7 में सबसे ज्यादा 41 फीसदी अप्रूवल इटली की पीएम जोर्जिया मेलोनी को मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को 37 फीसदी, कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को 29 फीसदी, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को 25 फीसदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को 23 फीसदी अप्रूवल रेटिंग मिली है।

बंगाल समेत 3 राज्यों में सीट बंटवारे पर कांग्रेस से बातचीत को तैयार ममता जानें कितनी सीट पर बनी सहमति



नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी है। यूपी में अखिलेश से सुलह के बाद अब ममता बनर्जी ने भी अपने तेवर नरम कर दिए हैं। पहले जहां ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी लेकिन, अब सूत्रों का कहना है कि तुणमूल कांग्रेस बंगाल, मेघालय में कांग्रेस के साथ सीट-बंटवारे पर बातचीत के लिए तैयार है। सीट शेयरिंग पर दोनों दलों के बीच फाइनल बात भी सामने आई है। देश में आम चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए औपचारिक सीट-बंटवारे समझौते पर मुहर लगाई थी। यूपी में अखिलेश ने कांग्रेस को उनकी पारंपरिक सीट अमेठी और रायबरेली समेत 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उठाने का ग्रीन सिग्नल दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी दिल बड़ा करते हुए एमपी में अखिलेश को एक सीट दी है। सपा और कांग्रेस के

इस समझौते से ठीक एक दिन बाद 22 फरवरी को ऐसे संकेत मिले हैं कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में भी गठबंधन कर सकती है। इसके लिए टीएमसी ने सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए हामी भरी है।

बंगाल से गुड न्यूज विपक्षी गठबंधन को करेगी बूस्ट?

पश्चिम बंगाल में टीएमसी का कांग्रेस के प्रति नरम रुख के लिए बड़ी राहत की खबर है जो उसे आगामी आम चुनाव से पहले बूस्ट करने जैसा है। विपक्षी गठबंधन को लेकर सामने आई यह जानकारी इस वक्त इसलिए भी अहम है क्योंकि, हाल ही में नीतीश कुमार ने जनता दल- यूनाइटेड को विपक्ष से अलग करते हुए एनडीए में अपना विलय किया। साथ ही बिहार में आरजेडी को किनारे करते हुए बीजेपी के साथ सरकार बना ली।

युवा किसान की मौत पर संगठन मना रहे ब्लैक डे, दिल्ली मार्च पर आज फैसला

हरियाणा में किसान नेताओं पर NSA लगाने का फैसला वापस

हरियाणा पुलिस ने कहा है कि वो किसानों के दिल्ली मार्च के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों की संपत्ति कुर्क करेगी और उनके बैंक खातों को भी सीज किया जाएगा।

कल रात पुलिस ने किसानों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (ह्र्) के तहत कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन आज इस आदेश को वापस ले लिया।

दूसरी ओर खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान की मौत के विरोध में आज किसान ब्लैक फ्राइडे मना रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान मजदूर मोर्चा के सदस्य अमरजीत सिंह मोहड़ी के घर पर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है। अंबाला पुलिस की ओर से जारी इस नोटिस में लिखा है कि मोहड़ी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और बिना अनुमति इसमें शामिल होने पर मोहड़ी की संपत्ति से भी भरपाई हो सकती है। नोटिस में मोहड़ी की संपत्ति और बैंक खातों की जानकारी मांगी गई है।

3 पुलिसकर्मियों की मौत, 30 जख्मी

पुलिस ने कहा कि किसान नेताओं के भड़काने पर शंभू बॉर्डर पर किसान पत्थरबाजी कर रहे हैं। इसके कारण 30 जवानों को चोटें आई हैं, एक पुलिसकर्मी को ब्रेन



हैमरेज हुआ है और 2 की मौत हो चुकी है।

पंजाब में ड्यूटी पर नैनात एक पुलिसकर्मी की मौत ज़िम में हुई है। पुलिस ने कहा कि आंदोलनकारियों ने जिन संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, उसका आंकलन किया जा रहा है, जिसकी भरपाई संपत्ति कुर्क कर और खाते सीज कर की जाएगी।

पंढर ने पंजाब सरकार को घेरा

पंढर ने कहा, शुभकरण सिंह की मौत के बाद पंजाब सरकार से

बातचीत हुई थी। हमारी सभी मांगें मान ली गई थीं। 14 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन पंजाब सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, इसलिए शुभकरण का शव अस्पताल में पड़ा है। पंजाब सरकार हमारे शहीदों की शहादत का अपमान कर रही है। यह निंदनीय है। मुझे नहीं लगता कि हम अभी शुभकरण का अंतिम संस्कार कर पाएंगे। सरकार के साथ बातचीत पूरी नहीं हुई है।दिल्ली कूच पर आज फैसला लेंगे किसानदु किसान शुभकरण

सिंह की मौत के बाद किसानों ने दिल्ली कूच को 2 दिन के लिए रोक दिया था। आज किसान-मजदूर मोर्चा बैठक कर आगे की रणनीति पर फैसला लेगा। हरियाणा के किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन (चट्टनी) ने भी आज बैठक बुलाई है। इसमें आंदोलन में सहयोग के तरीकों पर फैसला लिया जा सकता है। किसान नेता सरवण सिंह पंढर ने आज सभी किसानों से घरों और वाहनों पर काले झंडे लगाने की अपील की है।

वाराणसी में बोले पीएम मोदी

काशी तो संवरने वाला है..., पुल भी बनेंगे और भवन भी, मुझे तो जन-जन को संवारना है



पीएम मोदी ने कहा- काशी तो संवरने वाला है... रोड भी बनेंगे, ब्रिज भी बनेंगे, भवन भी बनेंगे लेकिन मुझे तो यहां जन जन को संवारना है, हर मन को संवारना है और एक सेवक बनकर संवारना है, साथी बनकर संवारना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। बीएचयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जिस काशी को समय से भी प्राचीन कहा जाता है, जिसकी पहचान को युवा पीढ़ी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है। ये दुष्प्र हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और यह विश्वास भी दिलाता है कि अमृत काल में सभी युवा देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

परीक्षा दौरान झुग्गी बस्ती पर एक्शन के खिलाफ पूर्व मंत्री

भोपाल में झुग्गी भदमदा बस्ती पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा मानव अधिकार आयोग जाएंगे। वे बताएंगे कि परीक्षा समय में बस्ती के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। पूर्व मंत्री का प्लान बस्ती जाकर लोगों से मुलाकात करने का भी है।

प्रदर्शनकारी किसानों पर सरकार हुई सख्त, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट हो रहे सीज, जुटाई जा रही जानकारी

नई दिल्ली। एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर सरकार ने सख्ती करने का फैसला किया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन में शामिल किसानों की प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट सीज किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय निवासियों से इस बात की जानकारी मांगी गई है कि क्या प्रदर्शन के दौरान उनकी किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए सरकार तरह-तरह के उपाय अपना रही है।



किसानों पर ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस के गोले भी बरसाए गए हैं। वहीं, खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन

के दौरान एक युवा किसान की मौत हो गई। इसके बाद किसानों ने प्रदर्शन में दो दिन के ब्रेक की

घोषणा की थी। फिलहाल आज किसानों के प्रदर्शन के ब्रेक का दूसरा दिन है। इस बीच यह भी जानकारी आई है किसानों ने दिल्ली की तरफ बढ़ने की पूरी योजना बना रखी है। इसके लिए किसान अपने साथ जेसीबी से लेकर और अन्य जरूरी इंतजाम लेकर चल रहे हैं। उधर, खनौरी बॉर्डर पर किसान की मौत के बाद गुस्सा भी काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ सरकार भी अपनी तरफ किसानों को मनाने के प्रयास में लगी है। इसके तहत बुधवार रात गन्ना खरीद का दाम बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी गुरुवार को किसानों को खास संदेश भेजा है।

सावधान जाहिर सूचना

ग्राम गोकन्या हल्का शिवनगर रा.नि.मं. सिमरोल तहसील महू जिला इन्दौर म.प्र खसरा न. 72 वा अन्य खसरो कृषि भूमि के सम्बन्ध मे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम गोकन्या हल्का शिवनगर रा.नि.मं. सिमरोल तहसील महू जिला इन्दौर म.प्र मे स्थित कृषि भूमि विजय पिता राम भरोसे तिवारी से छल कर फरेब से सोची समझी चाल चल कर जिसका खसरा नंबर 72 वा अन्य खसरो को लिख कर 8 विक्रय पत्रों के लिए कूटरचित भाषा लिख कर दस्तावेज तयार कर वा फर्जी चेको को दे कर जालसाजी और 420 से विक्रय पत्रों का पंजीयन करवाया गया है इन सभी के नाम इस प्रकार है सुमित प्रकाश पाटनी पिता मणिक चन्द पाटनी, अरुणा पाटनी पति सुमित प्रकाश पाटनी,अनिल कुमार पंवार पिता मोहन सिंह पंवार, राहुल जैन पिता राकेश जैन, आनंद कसेरा पिता लक्ष्मणदास कसेरा राकेश जैन पिता स्व.नवीन चन्द जैन,पार्वती जैन पति बक्षीराम जैन, पवन जैन पिता बक्षीराम जैन इन सभी के खिलाफ पुलिस में जांच चल रही है कोर्ट में केस पेंडिंग है अतः कृषि भूमि खसरा नंबर 72 वा अन्य खसरो का सौदा किया गया था जिसका भुगतान राशि चेको के माध्यम से की गई थी पर चैक अनादरण होने से सौदा 2018 में निरस्त किया जा चुका है जिसकी सूचना पेपर विग्यप्ति के माध्यम से पहले ही सूचना दी जा चुकी है अतः इन सभी विक्रय पत्रों के संदर्भ मे किसी भी व्यक्ति, संस्था या बैंक आदि से कर्ज हेतु प्राप्त करता है या इन रजिस्ट्री के माध्यम से विक्रये करता है तो इस की जवाब देयी किसान भूमि मालिक की नही होगी अतः होने पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी।

सिंगल कॉलम

मुफ्त की बिजली पड़ेगी महंगी, देअविवि के आईटी के प्रोफेसर्स-कर्मचारियों से होंगी वसूली

देवी अहिल्या विवि के इंजीनियरिंग कालेज आईटी कैंपस में रहने वाले शिक्षकों-कर्मचारियों पर मुफ्त की बिजली अब भारी पड़ने जा रही है। देअविवि ने प्रारंभिक जांच के बाद शिक्षकों और कर्मचारियों से लाखों की वसूली का निर्णय लिया है। इस बारे में कुलसचिव ने इंजीनियरिंग सेक्शन को आदेश जारी किया है। कैंपस में रहने वाले 18 से ज्यादा स्टाफ सदस्यों से करीब तीन-तीन लाख रुपये वसूले जाएंगे।खंडवा रोड पर आईटी कैंपस में रहने वाले शिक्षक-कर्मचारी के सरकारी आवास का बिजली बिल भी संस्थान चुका रहा था। आईटी के डायरेक्टर करीब दस वर्षों से विश्वविद्यालय के खाते से बिल जमा कर रहे थे। स्टाफ क्वार्टर्स में लगे बिजली मीटरों की रीडिंग न केवल बंद करवा दी गई थी बल्कि कई क्वार्टर्स में तो मीटर ही हटा दिए गए थे। नईदुनिया ने 28 नवंबर के अंक में मुफ्त की बिजली के घोटाले का खुलासा किया। विश्वविद्यालय ने जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी। कमेटी ने प्रारंभिक तौर पर प्रति निवास 45 से 47 हजार रुपये के बिल की वसूली की अनुशंसा विवि के कुलसचिव डा.अजय वर्मा को की। हालाँकि कमेटी की अनुशंसा पर सवाल खड़े हो गए। दरअसल, कमेटी में जांच के लिए सदस्य बनाए गए इंजीनियरिंग सेक्शन के प्रभारी डा.नागेंद्र सोहनी खुद ही उस कैंपस में रहते थे। इसके बाद रजिस्ट्रार ने फिर से जांच और आंकड़ा तय करने के निर्देश दिए। जांच में सामने आया कि कैंपस में रहने वाले लोगों में सिर्फ एक प्रोफेसर ऐसे हैं जो बिजली का बिल चुका रहे थे। बिल नहीं चुकाने वालों में एक नाम देअविवि की प्रोफेसर और प्रदेश सौनियर आइएएस अधिकारी की पत्नी का भी है। जांच कमेटी की अनुशंसा के बाद अब प्रति क्वार्टर बीते वर्षों के बिजली बिल के रूप में दो लाख 75 हजार रुपये से दो लाख 96 हजार रुपये तक का आंकड़ा रखा गया है। वसूली के आदेश जारी कर कुलसचिव ने इंजीनियरिंग विभाग को वसूली कर विश्वविद्यालय के खाते में जमा करवाने का निर्देश दिया है।

युवकों को होटल में बंधक बनाकर करते थे वसूली, ठेइछाड़ और दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देते थे

इंदौर। बाणगंगा पुलिस ने ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो युवकों को बंधक बनाकर अवैध वसूली करता था। गिरोह में होटल का मैनेजर और कर्मचारी भी शामिल हैं। इस गिरोह ने कई लोगों से वसूली करना कुबूला है। निशाने पर वो लोग होते थे, जो युवतियों के साथ टहलने या मिलने चले जाते थे।पुलिस के मुताबिक घटना कनक कारिडोर कालोनी स्थित होटल कुष्णा की है। आरोपित लोकेश यादव, धर्मराज उर्फ राज, वंश उर्फ भानजा, कलश, आदित्य उर्फ बाला और राज पन्नाकर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित लच्छू ठाकुर व अन्य की तलाश है। आरोपितों से मोबाइल, नकदी और दोपहिया वाहन जब्त हुए हैं। टीआइ नीरज बिरथरे के मुताबिक पहली घटना सौंदर नगर बंगाली चौराहा निवासी छात्र प्रशांत जैन के साथ हुई है। प्रशांत दोस्त मुस्कान के साथ गार्डन में बात कर रहा था। आरोपितों ने दोनों पर नजर रखी और मुस्कान के जाते ही प्रशांत को बुलाया। रूम में बंद कर पिटाई की और मोबाइल छीन लिया। आरोपितों ने फोन अनलाक कर ई-वालेट से करीब चार हजार रुपये ट्रांसफर कर लिए। कोरे कागज पर लिखवाया-छेड़छाड़ नहीं करूंगा आरोपितों ने प्रशांत को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। उससे रुपये लेने के बाद कोरे कागज पर लिखवाया कि वह युवती के साथ आया था। उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। प्रशांत जख्मी हो गया। मौका देख कर भागा तो आरोपितों ने उसकी शर्ट फाड़ दी और मोबाइल छीन कर डेटा डिलीट कर दिया। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा और पिता रवींद्र जैन, मां राधा को पूरी घटना बताई। उसने पुलिस को बताया-आरोपित एक अन्य युवक को भी बंधक बना कर पीट रहे थे।

इंदौर के खजराना में नगर निगम की अतिक्रमण हटाने पहुंची रिमूवल टीम

नगर निगम का रिमूवल विभाग गुरुवार को खजराना क्षेत्र में कार्रवाई करने उतरा। स्टार चौराहा से खजराना पुलिस थाने तक सड़क से अतिक्रमण हटाए गए। करीब चार घंटे चली कार्रवाई में नगर निगम के अमले ने 250 शेड, 150 ओटले, 15 से ज्यादा दुकानें जर्मीदोज किए। 70 से ज्यादा निगमकर्मियों की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान 20 ट्रक से ज्यादा मलबा निकला।कार्रवाई के दौरान कई जगह विवाद की स्थिति भी बनी, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल होने की वजह से विवाद टल गया। कार्रवाई से पहले दुकानदारों को उनका अतिक्रमण हटाने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया। निगम के अमले को देखते हुए कई जगह तो व्यापारियों ने खुद ही अपना अतिक्रमण हटा भी लिया। निगम का अमला गुरुवार सुबह करीब 11.30 बजे स्टार चौराहा पहुंचा। टीम के साथ अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा, सहायक रिमूवल अधिकारी बबलू कल्याण भी थे। टीम ने पहले तो व्यापारियों को चेतावनी दी कि वे खुद ही अपना अतिक्रमण हटा लें, वरना निगम कार्रवाई करेगी। इसके बाद कई जगह व्यापारी खुद ही अतिक्रमण हटाने लगे। 12 बजे के आसपास निगम के अमले ने जमजम चौराहा से कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले दुकानों के बाहर बने टिन शेड को हटाया गया। इसके बाद ओटलों को निशाने पर लिया गया।

स्कूली शिक्षा में पिछड़ा इंदौर 29 से 48वीं पायदान पर लुढ़का

सिटी चीफ इंदौर

शिक्षा के मामले में इंदौर का नाम पूरे देशभर विख्यात है, लेकिन स्कूली शिक्षा की बात करें तो प्रदेश के जिलों में ही इंदौर काफी पिछड़ गया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत सभी जिलों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में इंदौर जिला 48वें नंबर पर है। वहीं इंदौर संभाग सबसे पीछे यानी 10वें नंबर पर है। सात बिंदुओं पर हुए मूल्यांकन में इंदौर बी स्थिति काफी खराब है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति साक्षरता अभियान, टीचर ट्रेनिंग, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन में रही।राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी रैंकिंग में पिछले साल इंदौर 29वें पायदान पर था। इस बार 19 पायदान पिछड़कर 58.76 फीसदी अंक के साथ 48वें नंबर पर आ गया है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के नाते यहां शिक्षा विभाग के आला अफसर निरीक्षण करने आते हैं। बजट में भी कमी नहीं रहती है। बावजूद शिक्षा गुणवत्ता से लेकर स्कूल इमारत अधोसंरचना तक में इंदौर जिले की स्थिति खराब है। संभाग भी सबसे पीछे 60.77 फीसदी अंक के साथ आखिरी पायदान पर है।

प्रशिक्षण को गंभीरता से नहीं लेते शिक्षक

राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के तहत जारी की गई रैंकिंग में इंदौर जिले



की कई कमियां सामने आई हैं। इस बार जिले में प्रारंभिक कक्षा में महज 11 हजार बच्चों का ही प्रवेश हो पाया। प्राथमिक स्तर के स्कूलों में बच्चों को शब्द पढ़ना, बोलना, जोड़-घटाव, गिनती आदि तक समझने और बोलने में दिक्कत है। इसका सीधा मतलब है कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से बचे रहे। बच्चों को बेहतर शिक्षण के लिए सालभर शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है, लेकिन कई शिक्षक इस प्रशिक्षण को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हर साल स्कूलों की मरम्मत के लिए लाखों रुपए जारी होते हैं। लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं, जहां भवन अधोसंरचना, मूलभूत सुविधाएं काफी कम

हैं। कई स्कूलों में फर्नीचर तक नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं, जहां टाटपट्टी पर बैठकर पढ़ाया जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन जिले में इन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाया। यही कारण है कि कई स्कूलों में दो साल बाद भी गणवेश वितरण तक नहीं हो पाया है। कई बच्चे पात्र होने के बाद छात्रवृत्ति से वंचित हैं। जिले में इस बार 75 हजार से अधिक बच्चे ड्राप आउट हैं। सत्र बीतने को है, लेकिन जिम्मेदार अफसर इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में असमर्थ रहे हैं।

सात गांव के तीन हजार कैमरे खंगाले 54 लोगों के फिंगर प्रिंट ले चुकीं पुलिस

सिटी चीफ इंदौर

कनाड़िया थाना के सामने हुई डकैती में पुलिस खाली हाथ है। पिछले 12 दिनों से सिर्फ सीसीटीवी कैमरें खंगाले जा रहे हैं। पुलिसवाले डेर और झोपड़ियों में रहने वालों से पूछताछ कर फिंगर प्रिंट ले लेते हैं। जांच अब पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) डेटा के भरोसे से बैठे हैं।10 और 11 फरवरी की दरमियानी रात तिलकनगर (बी) में वकील दांगी के घर में डकैती हुई थी। सात से ज्यादा सशस्त्र बदमाश वकील (बैंड संचालक), उनकी पत्नी, बेटे से मारपीट कर स्वर्ण आभूषण और नकदी लूट कर ले गए। पुलिस को घटनास्थल से डकैतों की अंगुलियों के निशान और सीसीटीवी फुटेज तो मिल गए लेकिन यह जानकारी नहीं मिली कि वाददात में कौन-सा गिरोह है। पिछले 12 दिनों से बिचौली हफ्सी, बिचौली मर्दाना, बड़ियाकीमा, हरनिया बडी, कनाड़िया सहित सात गांवों में छानबीन कर ली। खेत और निर्माणाधीन मकानों में चौकीदारी करने वाले 54 लोगों के फिंगर प्रिंट ले लिए। डेर और फेरी लगाकर सामान बेचने वाले 250 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस अभी तक खाली हाथ ही है। एसीपी कुंदन मंडलोई के मुताबिक चार टीमों दिन-रात जांच में जुटी हैं। तीन हजार से ज्यादा कैमरों को खंगाला जा चुका है।



एक टीम से चूक न हो इसलिए दूसरी टीम दोबारा जांचती है। डकैतों के फुटेज तो मिले लेकिन यह पता नहीं चला कि किस रास्ते से आए और किस रास्ते से भागे। पुलिस ने पांच किमी के दायरे में जांच कर ली। अब अन्य जिलों की पुलिस से सहाज साझा कर रहे हैं। सीरियल लुटेरों का हुलिया मिलाकर हो रही पूछताछ लसूडिया पुलिस लुटेरों को नहीं पकड़ पाई। साफ-सुथरे फुटेज मिलने के बाद भी पुलिस खाली हाथ है। लुटेरों ने महालक्ष्मी नगर में डाक्टर पूजा गुप्ता और वृद्धा से चेन लूटी थी। टीआइ तारेश सोनी के मुताबिक पुलिस ने 40 से ज्यादा से लोगों से पूछताछ कर ली है। दो किमी के दायरे में डेढ़ सौ से ज्यादा कैमरों के फुटेज निकाले हैं। उन लोगों से पूछताछ कर ली जिनका लुटेरों से हुलिया मिलता है। संदेहियों से क्रास पूछताछ की जाती है। घटना के वक्त कहां थे, यह भी जांच में लिया गया है।

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी चयन परीक्षा के नतीजे घोषित

सिटी चीफ इंदौर

इंदौर। मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग (पीएससी) ने गुरुवार शाम आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी चयन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। कुल 692 पदों के लिए दो चरणों में चयन प्रक्रिया हुई थी। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद अंतिम परिणाम जारी किया गया है। अभी सफ 543 अभ्यर्थियों को ही मुख्य चयन सूची में स्थान दिया गया है।इसमें भी अनुसूचित जनजाती वर्ग के 28 व दिव्यांग श्रेणी को मिलाकर कुल 59 योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण 543 उम्मीदवारों की ही चयन सूची



जारी की गई है। शेष 13 प्रतिशत पदों के लिए चयन सूची ओबीसी आरक्षण पर लंबित कानूनी वाद में अंतिम निर्णय आने के बाद घोषित होगी।

मप्र बोर्ड परीक्षा के पहले चरण में 90 हजार कापियों का मूल्यांकन कार्य शुरू

सिटी चीफ इंदौर

माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिम) की बोर्ड परीक्षा में अब तक 17 पेपर हो चुके हैं। इधर, गुरुवार से शासकीय मालव कन्या उमावि में मूल्यांकन कार्य भी शुरू हो चुका है। पहले चरण में 90 हजार कापियां जांच होने के लिए मूल्यांकन केंद्र पहुंची गई हैं। पहले दिन 10वीं और 12वीं कक्षा के हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी विषय की कापियां जंचना शुरू हो चुकी हैं। पहले दिन मूल्यांकन के लिए 60 शिक्षक पहुंचे। बता दें कि मूल्यांकन कार्य के लिए जिलेभर से 800 से अधिक शिक्षकों ने पंजीयन कराया है।मालव कन्या उमावि को जिला मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। मूल्यांकन के लिए करीब 800 शिक्षकों को मूल्यांकनकर्ता बनाया गया है। किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसलिए जिन बीस कक्षाओं में मूल्यांकन कार्य



किया जाना है। सभी कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पहले दिन 60 मूल्यांकनकर्ता कापियां जांचने के लिए पहुंचे। धीरे-धीरे यह संख्या

बढ़ती जाएगी। जब तक बोर्ड परीक्षाएं चलेंगी, तब तक दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक मूल्यांकन होगा। अगले सप्ताह पूरा होगा पहला

चरण परीक्षा खत्म होने पर सुबह 10 से शाम 6 बजे तक मूल्यांकन कार्य होगा। हर एक मूल्यांकनकर्ता को

ब्रांडेड गारमेंट की नकल का गढ़ बना इंदौर बसों से हो रही हैं देशभर में आपूर्ति

प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर नकली ब्रांडेड गारमेंट निर्माण का गढ़ बन गया है। नकल ऐसी हो रही है कि कोई भेद नहीं कर सकता। आनलाइन बाजार में इंदौर में बना नकली ब्रांडेड गारमेंट देशभर में सप्लाई हो रहा है। नकली ब्रांड को हबहु गढ़ने के लिए कच्चा माल, जिसमें टैग से लेकर लोगो वाले रिबिट तक चीन से आ रहे हैं। तीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शिकायत पर एक कारखाना पकड़ा गया है लेकिन अब तक सैकड़ों करोड़ रुपये का माल बाजार में खपाया जा चुका है। कारोबार में शत-प्रतिशत टैक्स की चोरी भी हो रही है। ऐसे में अब जीएसटी भी इस जांच में कुदने जा रहा है।बुधवार को तीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शिकायत पर पुलिस ने तिलकपथ पर नकली गारमेंट बनाने वाले कारखाने दिशा एपेरल्स का खुलासा हुआ है। मौके से चार कंपनियों के नकली गारमेंट और कच्चा माल जब्त भी हुआ। इनमें लिवाइस, प्यूमा, केल्विन क्लेन (सीके) अंडर आर्मर शामिल है। इन नकली गारमेंट में न सिर्फ बाहरी कंपनियों के नाम के टैग नहीं लगाए जा रहे बल्कि अंदरूनी डबल टैगिंग से लेकर धागे और जींस में लगने वाली कापर रिबिट को भी हबहु कापी किया जा रहा है। नकल के लिए कच्चा माल और लेबल चीन में बनकर बांग्लादेश के रास्ते इंदौर तक पहुंच रहे हैं। कारखाने का संचालन करने वाला पहले असम में कामकाज कर रहा था। ऐसे में बांग्लादेश के रास्ते इंदौर तक नकली टैग लाए जा रहे थे। मप्र और इंदौर को इसलिए चुना जा रहा है क्योंकि बीच में होने के कारण यहां से देशभर में आपूर्ति करना सुलभ है। बाजार के सूत्रों के अनुसार सिर्फ आनलाइन गारमेंट बेचने वाली फर्म ही नहीं बल्कि कुछ बड़े गारमेंट व्यापारी जो कंपनी से भी जुड़े है वे भी इस माल को मंगवा रहे थे। पूरा सौदा बिना बिल सिर्फ कच्ची पर्तियां पर हो रहा है। जींस और गारमेंट पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। कंपनी से खरीदे गए थोड़े असली माल के बिल के सहारे उससे दस गुना ज्यादा माल बाजार में आनलाइन और काउंटर से बेच दिया जाता है। टैग के लिए डार्क रूम नकली गारमेंट बनाने वाले कपड़ा काटने के बाद उसकी सिलाई से लेकर इस्त्री तक जाब वर्क पर दूसरों से करवाते हैं। छोटे-छोटी दुकानों और घरों में चलने वाले कारखानों में कपड़ा काटकर सिलने भेजा जाता है। इसके बाद ब्रांड की टैगिंग लगाने का काम नकली माल बनाने वाले अपने कारखाने में करते हैं जिसे डार्क रूम कहते हैं। टैग के साथ अंदर लगने वाले बार कोड को भी कापी किया जाता है। इसके बाद सिर्फ इसी तरह छोटे-छोटे दुकान या घरों में इनकी एंजिड से धुलाई और इस्त्री होती है। हिस्सों में होने वाले निर्माण के कारण न तो नकली माल नजर आता है और न बनाने वाले को पता होता है कि वह कापी बना रहा है छूट वाले कपड़ों में 75 प्रतिशत नकली गारमेंट कारोबारियों के अनुसार इंदौर के एक कारखाने से ही छापामार टीमो ने नौ गाड़ी माल जब्त किया है। इसमें जींस-टीशर्ट से लेकर लोअर व स्पोर्ट्स वियर भी शामिल है। कई गारमेंट डिस्ट्रिब्यूटर जोकि रिटेल व्यापारियों को माल सप्लाई करते हैं और आनलाइन गारमेंट भी बेचते हैं वे ही नकली गारमेंट खरीदते हैं।डट दिखाकर असल बताकर बेचे जाते हैं।

मुंबई में 200 करोड़ का गबन करने वाली संस्था पर एफआइआर

सिटी चीफ इंदौर

चर्चित श्री महाकाली को-आपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड पर एमजी रोड पुलिस ने एफआइआर दर्ज की है। घोटाले में शामिल सात लोगों को पुलिस ने नामजद आरोपित बनाया है। करीब दो सौ करोड़ का घोटाला कर चुकी इस संस्था के विरुद्ध मुंबई और धार में पूर्व से प्रकरण दर्ज है।टीआइ विजय सिसोदिया के मुताबिक ज्योति केएल माहेश्वरी द्वारा श्री महाकाली ग्रुप आफ कंपनीज (मुंबई) की रजिस्टर्ड संस्था श्री महाकाली को-आपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि. के कर्ताधर्ता पंकज सोलंकी, रितेश दिलीप कुमार सिकलीगर, भारती सिकलीगर, विशाल शाह, हर्षिक सिकलीगर, शुभम तिवारी और केशवलाल गोयल के विरुद्ध शिकायत दर्ज



करवाई थी। सुखसागर अपार्टमेंट एमजी रोड निवासी ज्योति माहेश्वरी को पोलिस द्वारा संस्था की जानकारी दी थी।

उनकी धार और इंदौर में संस्था का कार्य संचालने वाले पंकज सोलंकी व केशवलाल गोयल से मुलाकात हुई और योजना की जानकारी दी। आरोपितों ने उनके द्वारा बताए खातों में करीब 12

लाख 50 हजार रुपये जमा करवा लिए गए। बाद में संस्था के कर्ताधर्ता अलग-अलग शहरों में गबन कर फरार हो गए। मुंबई के वपई से संचालित इस संस्था के विरुद्ध आर्थिक अपराध ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) मुंबई और धार पुलिस ने भी एफआइआर दर्ज की। संस्था पर करीब 200 करोड़ रुपये का गबन करने का आरोप है।

इंदौर में पुलिया पर 90 डिग्री घूमी कार, 10 फीट गहराई में गिरी

सिटी चीफ इंदौर

युवती का जन्मदिन मनाने जा रहे युवक कार सहित पुलिया से नीचे जा गिरे। कार इतनी रफ्तार में थी कि गिरने से तीन टुकड़े हो गए। हादसे में कार में बैठे पांच लोगों को चोट आई है। एक युवती के पैर में फ्रैक्चर भी हुआ है। हालांकि अब वो पुलिस केस से इन्कार कर रहे हैं।तेजाजी नगर टीआइ देवेंद्र मरकाम के मुताबिक घटना बुधवार रात करीब ढाई बजे खंडवा रोड की है। भंवरकुआं क्षेत्र में रहने वाले युवक-युवती कार एमपी 09 सीएम 2113 से आइटी पार्क की तरफ से खंडवा रोड की ओर जा रहे थे। अचानक अनियंत्रित कार पुलिया से नीचे जा गिरी। कार के पहिये और बाड़ी टूट कर अलग हो गए। टीआइ के मुताबिक कार में पायल नागर, खुशी, विकास, वैभव और मोहित नामक युवक थे। घटना के बाद भी युवकों ने पुलिस को खबर नहीं दी। अस्पताल पहुंचने पर पुलिस को जानकारी मिली। मूलतः बरोठा (देवास) निवासी पायल भंवरकुआं क्षेत्र में रहती है। बुधवार को उसका जन्मदिन था। वह दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने निकली थी। उसने बयान में



बताया कि कार विकास चला रहा था। आगे चल रहे ट्रक के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए थे। विकास ने बचने के चक्कर में कार पूरी मोड़ दी और पुलिया से नीचे गिर गई। पायल ने पुलिस केस से भी इन्कार कर दिया। 10 दिन में दूसरा हादसा तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में दस दिन के भीतर दूसरा हादसा हुआ है। 12 फरवरी को इंजीनियर की कोस्तुभ लांबे की हादसे में मौत हुई थी। कोस्तुभ जिस कार में बैठा था वह डिवाइडर से टकरा कर 100 फीट दूर चली गई थी। कोस्तुभ भी कार से दूर जा गिरे और कार का बंपर और पहिये तक अलग अलग हो गए।

प्रतिदिन अधिकतम 45 कापियां जांचना होगी। मूल्यांकनकर्ताओं को 10वीं कक्षा की कापी जांचने के प्रति कापी के 15 रुपये और 12वीं में 16 रुपये रुपये मिलेंगे। मूल्यांकनकर्ता द्वारा कापी जांचने में गलती की जाती है और कम या अधिक अंक दिए तो प्रति अंक के लिहाज से 100 रुपये काट लिए जाएंगे। पहले चरण का मूल्यांकन आगामी सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा।

मूल्यांकन केंद्र प्रभारी बबोिता हयारण ने बताया कि पहले दिन कापियों की संख्या काफी कम थी, इसलिए 60 मूल्यांकनकर्ताओं को ही बुलाया गया है। कापियों की जांच के दौरान मूल्यांकनकर्ताओं के मोबाइल अलग रखवा लिए जाते हैं। हर एक कक्ष की सतत निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्म भी तैनात है।

आंचल बालगृह को विदेश से मिले दो करोड़ रुपये बच्चियों का मतांतरण करवाने का है आरोप

सिटी चीफ भोपाल
परवलिया थाना क्षेत्र के तारासेवनिया में अवैध रूप से संचालित हो रहे आंचल बालगृह को विदेश से दो करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। यह खुलासा कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा कराई गई जांच में हुआ है। कलेक्टर ने बताया कि बालगृह के संचालक अनिल मैथ्यू को मिलने वाले पैसों के लेखाजोखा में विदेशी फंडिंग का रिकॉर्ड मिला है। वहीं संचालक बालागृह के संबंध में अनुमति प्रस्तुत नहीं कर पाया है। विदेशी फंडिंग की पुष्टि होने पर रिपोर्ट को गृह विभाग भेज दिया गया है। अब यह विदेशी फंड कहाँ से आई, किस माध्यम से आया इसकी जांच विभाग द्वारा ही करवाई जा सकती है। बता दें कि बालगृह संचालक अनिल मैथ्यू के खिलाफ धर्मांतरण कानून के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल मैथ्यू जमानत पर रिहा



हैं।परवलिया सड़क थाना इलाके के ग्राम तारासेवनिया मे संचालित आंचल बालगृह में मिली बालिकाओं ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अपने बयानों में उन्होंने बताया कि बालिकाओं से आश्रम की साफ-सफाई करावाई जाती थी। साथ ही ईसाई धर्म के अनुसार पूजा प्रार्थना करने हेतु उत्प्रेरित / बाध्य किया जाता था।

बयान दर्ज करने के बाद रविवार को बाल गृह संचालक अनिल मैथ्यू के खिलाफ दर्ज एफआइआर में धारा 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम भी बढ़ा थी। साथ ही मैथ्यू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि चार जनवरी को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो

एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के दल ने आंचल बाल गृह का औचक निरीक्षण किया था। पता चला कि संस्था नियम विरुद्ध एवं अवैध रूप से संचालित हो रही थी। बाल संरक्षण अधिकारी रामगोपाल यादव की शिकायत पर बाल गृह के संचालक आरोपित अनिल मैथ्यू के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा -34,42 एवं 75 के तहत केस दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान बालिकाओं से पृछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि आंचल बाल गृह में उनसे भवन की साफ सफाई एवं अन्य कार्य कराये जाते थे। साथ ही ईसाई धर्म के अनुसार पूजा प्रार्थना करने हेतु उत्प्रेरित / बाध्य किया जाता था। जिस पर धारा 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई। रविवार को गोविंदपुरा निवासी 49 वर्षीय अनिल पुत्र पीजे मैथ्यू को गिरफ्तार कर लिया गया।

भोपाल नगर निगम का नवाचार शौचालय का उपयोग करने पर मुफ्त मिलेगी चाय

सिटी चीफ भोपाल
महापौर मालती राय ने गुरुवार को नगर निगम मुख्यालय के नीचे स्थित आइएसबीटी परिसर में अत्याधुनिक स्मार्ट टॉयलेट का लोकार्पण किया। खास बात यह है कि इस शौचालय का उपयोग करने वाले को चाय या पानी की बोतल निशुल्क मिलेगी। यह पूरी तरह स्वाचालित होगा।अधिकारियों ने बताया कि इस आधुनिक शौचालय में वाईफाई, एसी, गर्म व ठंडे पानी की सुविधा और स्नान के लिए शॉवर लगाए गए हैं। इसके साथ ही यहां खानपान की व्यवस्थाएं भी रहेंगी। हालांकि शौचालय के लिए 10 रुपये और स्नानघर के लिए 30 रुपये का शुल्क चुकाना होगा। इसके बदले उपभोक्ता यहां से एक चाय या 10 रुपये वाली पानी की बोतल ले सकेंगे। यदि कोई चाय



या पानी की बोतल खरीदता है, तो वह शौचालय का निशुल्क इस्तेमाल कर सकेगा। पीपीपी मोड पर होगा संचालन स्मार्ट टायलेट और खानपान ग्रह का संचालन पीपीपी मोड पर किया जा रहा है। इसके बनाने का खर्च संचालन करने वाली संस्था ने वहन किया

है। वहीं मेटेनेस भी उसी को देना होगा। साथ ही नगर निगम को इससे एक निश्चित किराया मिलेगा। यदि शौचालय के बाद कोई चाय नहीं पीता तो उसे पाईट दिए जाएंगे। जिसे मोबाइल में दिखाकर लोग दूसरे आउटलेट में भी चाय पी सकेंगे।

तपिश पर लगाम, पांच दिन में 5.5 डिग्री सेल्सियस लुढ़का दिन का पारा



सिटी चीफ भोपाल
राजधानी में बसंत पंचमी के बाद से सूरज के तेवर तीखे होने लगे थे। जिसके चलते दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने का सिलसिला शुरू हो गया था। तेज हवाएं चलने के बाद भी धूप में चुभन महसूस होने लगी थी।18 फरवरी को दिन का तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस एवं रात का तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। जो इस माह के सबसे अधिक तापमान रहे। उसके बाद हवाओं का रुख बदलने से तापमान लुढ़कना शुरू हो गया। जिसके चलते 22 फरवरी को अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री और रात

का तापमान 14.6 डिग्री पर आ गया। इस तरह पांच दिन में दिन का तापमान 5.5 डिग्री एवं रात के तापमान में 4.2 डिग्री तक की गिरावट हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शुक्रवार को भी तापमान में कुछ और कमी आ सकती है।मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में हवाओं का रुख उत्तर-पश्चिमी बना हुआ है। दोपहर के समय 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इस वजह से तापमान में गिरावट हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 26 फरवरी को शहर में वर्षा होने की भी संभावना है।

मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा रही बेअसर अब न्याय यात्रा में जोर लगाएंगे राहुल गांधी

सिटी चीफ भोपाल
लोकसभा चुनाव के पहले निकल रही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भले ही मध्य प्रदेश कांग्रेस को अच्छे परिणाम की आस है लेकिन बीते साल निकली भारत जोड़ो यात्रा यहां चुनावी परिणाम की दृष्टि से बेअसर रही थी। वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश की जिन 22 विधानसभा क्षेत्रों से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उनमें से 18 सीटें भाजपा ने जीतीं।इसमें पांच एसटी वर्ग के लिए सुरक्षित सीटें भी थीं। इसमें से भी कांग्रेस को दो पर ही जीत मिलीं। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी फिर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे। प्रदेश में आदिवासी वर्ग का भरोसा जीतने के लिए शिवपुरी में आदिवासी संवाद होगा तो बदनावर में आदिवासी न्याय सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। बता दें, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से छह एसटी वर्ग के लिए सुरक्षित हैं।



विधानसभा चुनाव के परिणाम के आलोक में भारत जोड़ो यात्रा को देखें तो यह पूरी तरह बेअसर रही थी। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर-मालवा जिले के विधानसभा क्षेत्रों से होकर यात्रा गुजरी थी। बुरहानपुर, नेपानगर (एसटी), खंडवा (एसटी), पंधाना (एसटी), मांधाटा, बड़वाह, भीकनगांव (एसटी), महेश्वर, भगवानपुरा (एसटी), आंबेडकर नगर महू, राऊ, इंदौर-एक, इंदौर-दो, इंदौर-तीन, इंदौर-चार, सांवेर, उज्जैन दक्षिण, उज्जैन उत्तर,

घटिया, तराना, सुसनेर और आगर विधानसभा क्षेत्रों से यात्रा गुजरी थी। इनमें से एसटी वर्ग के लिए सुरक्षित भगवानपुरा और भीकनगांव के साथ सुसनेर सीट कांग्रेस ने जीती। शेष सभी सीटों पर भाजपा ने कांग्रेस को हराया। बता दें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में दो मार्च को राजस्थान के धौलपुर से प्रवेश करेगी और सात मार्च को फिर राजस्थान पहुंचेगी। इस बार जो मार्ग निर्धारित किया गया है, उसमें ग्वालियर-चंबल और मालवा

अंचल की मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, देवास (एससी), उज्जैन (एससी), धार (एसटी) और रतलाम (एसटी) लोकसभा सीटें आएंगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने धार में बढ़त बनाई तो रतलाम में मुकाबला बराबरी का रहा। शेष सभी लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों में भाजपा काफी आगे रही। मालवा अंचल की कई सीटों पर आदिवासी मतदाता परिणाम प्रभावित करने की स्थिति में है। यही कारण है कि राहुल की बड़ी सभा धार जिले के बदनावर में रखी गई है। धार जिले की सात सीटों में से पांच कांग्रेस ने जीती हैं। विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश एसटी वर्ग के लिए सुरक्षित 47 सीटों में से कांग्रेस 22 सीटें जीतीं। वर्ष 2018 के चुनाव के मुकाबले भी कांग्रेस को आठ सीटों को नुकसान हुआ। भाजपा ने इस बार 24 सीटें जीती हैं। एक सीट भारत आदिवासी पार्टी को मिली है।



उज्जैन में 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा पर प्रज्ज्वलित किए जाएंगे 27 लाख दीप, बनेगा विश्व रिकॉर्ड

भोपाल-उज्जैन में आगामी 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा के अवसर पर आयोजित शिवज्योति अर्पणम दीपोत्सव कार्यक्रम में 27 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसमें 25 हजार वॉलेंटियर, 200 से ज्यादा सामाजिक संगठन, एनएसएस, एनसीसी के छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता, आमजन मिलकर क्षिप्रा नदी के सभी घाटों पर दीप प्रज्वलन करेंगे और विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार शाम को उज्जैन में कार्यक्रम के लिये गठित परामर्शदात्री समिति की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अच्छे काम की शुरुआत होते ही लोग जुड़ते चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलन की परम्परा है। दीप ज्योति परमात्मा से जोड़ती है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि आगामी 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा एवं उज्जैन गौरव दिवस पर शिवज्योति अर्पणम कार्यक्रम में सहभागी बनकर धार्मिक, सांस्कृतिक परम्परा को समृद्ध करें। उन्होंने कहा कि शिवज्योति अर्पणम कार्यक्रम में उज्जैन के सभी धर्मप्राण नागरिक सहभागी बनकर विष्व रिकार्ड बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि इस बार भूखी माता मन्दिर घाट पर दीप प्रज्वलन किया जाएगा। रामघाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। सार्वजनिक स्थलों एवं घर-घर दीप प्रज्वलन कर इस दीपोत्सव को उज्जैनवासी यादगार

बनाएंगे। डॉ. यादव ने उज्जैन के नागरिकों के सहयोग की चर्चा करते हुए कहा कि जब विक्रमोत्सव 20 वर्ष पहले शुरू किया गया था तो बहुत छोटा स्वरूप था। उज्जैन के नागरिकों के सहयोग से आज भव्य स्वरूप ले लिया है। उन्होंने कहा कि उज्जैन को विक्रमादित्य के रूप में ऐसा राजा मिला जो विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेने का सामर्थ्य रखता था। उन्होंने विक्रमादित्य के गौरवाशाली इतिहास को बताते हुए कहा कि आज रूस और अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश भी आज सनातन संस्कृति की वजह से भारत का सम्मान करते हैं। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को जाता है। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उज्जैन के विकास के लिये कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। प्रारम्भ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महन्त रामेश्वरदास, प्रजापति ब्रह्मकुमारी उषा दीदी एव अन्य साधु-सन्तों का पुष्पगुच्छ भेंटकर आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम की रूपरेखा नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक ने बताई। इस अवसर पर महापौर मुकेश टटवाल, विवेक जोशी, बहादुर सिंह बोरमुंडला, पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती, श्याम बंसल, सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्रसिंह अरोरा, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मध्य प्रदेश के 176 गोदामों को किया गया ब्लैक लिस्टेड

सिटी चीफ भोपाल
मध्य प्रदेश में मार्च के अंतिम सप्ताह से गेहूँ की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होगी। करीब 100 लाख मीट्रिक टन खरीदी के हिसाब से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन प्रदेश के 176 गोदामों पर न तो उपार्जन होगा और न ही इनमें गेहूँ का भंडार किया जाएगा। कीट लगा खाद्यान्न रखने, सेंट्रल पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न देने में आनाकानी करने, समय पर न खोलने सहित अन्य गड़बड़ियों के कारण 176 गोदामों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। यह कार्रवाई भारतीय खाद्य निगम के निर्देश पर गुरुवार को मध्यप्रदेश व्हेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिंग कॉर्पोरेशन (राज्य भंडार गृह निगम) द्वारा की गई है। प्रदेश के जिन 176 व्हेयरहाउस और गोदाम को ब्लैक लिस्टेड किया है, उनमें खंडवा जिले के दो

व्हेयरहाउस शामिल हैं। एक पुनासा के पास पामाखेड़ी का मां नर्मदा व्हेयरहाउस है, जहां एफसीआई ने एप्रोच रोड की समस्या बताई। वहीं दूसरा व्हेयरहाउस खालवा का दिव्यशक्ति है, जो जनजातीय मंत्री कुंवर विजय शाह का है। इस व्हेयरहाउस में तौलकांटे में गड़बड़ी होना बताया गया है। गौरतलब है कि जबलपुर के गोदामों में गुणवत्ताहीन धान पाए जाने के मामले को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पिछले दिनों उपार्जन नीति को लेकर आयोजित बैठक में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने बताया था कि कुछ गोदाम संचालकों द्वारा सेंट्रल पूल में खाद्यान्न का उठाव करने में अवरोध उत्पन्न किया गया। गोदामों को समय पर नहीं खोला, पहुंच मार्ग को जानबूझकर खराब किया और कीटोपचार नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि

गोदामों में रखा खाद्यान्न कीटग्रस्त हो गया। निगम ने ऐसे गोदामों की सूची देते हुए इनमें उपार्जन केंद्र न खोलने और भंडारण नहीं करने के लिए निर्देशित किया था। इस आधार पर राज्य भंडार गृह निगम ने गुल्बर्गा को सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा कि वर्ष 2024-25 में गेहूँ उपार्जन के दौरान उन गोदामों में न तो उपार्जन केंद्र खोले जाएं और न ही भंडारण किया जाए, जिन पर भारतीय खाद्य निगम ने आपत्ति जताई गई है। दरअसल, सेंट्रल पूल में समय पर परिदान न होने से खाद्यान्न के खराब होने की आशंका होती है और उसका पूरा वित्तीय भार राज्य सरकार के ऊपर आता है। ब्लैक लिस्टेड प्रमुख गोदाम भोपाल- मूलचंद, ज्ञानवी, गिरिधर, बीएम और राजेश्वरी व्हेयरहाउस। इंदौर- तुलसी नारायण गर्ग साइलो, ज्योति मिल, लक्ष्य, रघुवंश एग्रो फूड साइलो।

मध्य प्रदेश के भगवान सिंह ने माइनस 45 डिग्री तापमान में पूरी की 21 किमी की मैराथन

सिटी चीफ भोपाल
नाम भगवान सिंह कुशवाहा। उम्र 50 वर्ष। शौक पर्वतों की ऊंचाई को छूना, ताकि हौसला हमेशा उनसे ऊंचा बना रहे। ये हैं दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही हैं। वह अपनी साहसिक गतिविधियों के लिए पहचाने जाते हैं। इसके साथ ही इन्होंने एक और उपलब्धि प्राप्त की है।पिछले दिनों दुनिया की सबसे ऊंची जमी झील पैंगोंग में आयोजित मैराथन में हिस्सा लेकर गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज कराया है। उन्होंने 14,273 फीट की ऊंचाई और -35 से -45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 21 किमी की हाफ मैराथन पूरी की। लद्दाख की पैंगोंग झील मैराथन को गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड के रूप में दर्ज किया गया है। द लास्ट रन के नाम से प्रसिद्ध इस मैराथन में इस वर्ष सात देशों से 120 धावकों ने हिस्सा लिया। प्रदेश से भगवान सिंह कुशवाह अकेले थे। मैराथन पूरी करने के बाद धावक ने एक पोस्ट में लिखा कि %यह सफलता आप सभी की दुआओं से प्राप्त की है। यह अलग तरह का



अनुभव रहा। मैराथन के दौरान हवा के साथ बर्फवारी इतनी अधिक थी कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ऐसे में संयम रखा और धीरे-धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। उन्होंने नवदुनिया को बताया कि मैराथन के दौरान पैंगोंग झील 21 किमी की दौड़

बेहद सर्द बफीली हवाओं के चलते ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इसलिए धीरे-धीरे दौड़ने की योजना पर काम किया और सफलतापूर्वक अपनी दौड़ पूरी करने का फैसला लिया। भारतीय सेना के सहयोग से मैराथन बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील पैंगोंग पर मैराथन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। इसे पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन भी कहा जाता है। इसमें 21 और 10 किलोमीटर श्रेणी की दो मैराथन में सात देशों के 120 धावकों ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने लद्दाख प्रशासन और 14 कोर भारतीय सेना के सहयोग से किया।

हिमालय के ग्लेशियरों के बारे में जागरूकता फैलाना उद्देश्य

उन्होंने बताया कि इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य तेजी से पिघल रहे हिमालय के ग्लेशियरों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस मैराथन को थिएस्टून टाइटल दिया गया, जिसका अर्थ है ग्लोबल

वार्मिंग के प्रभाव के कारण जमी हुई पैंगोंग झील पर यह आखिरी दौड़ हो सकती है। मैराथन का आयोजन केंद्र के श्वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में स्थायी शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना और विकास प्रयासों में तेजी लाना है।

साइकिल है उनका वाहन

एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान अपने दाहिने पैर के अंगुठे और चार अंगुलियां गंवां दी थीं। सुनने में भी समस्या आने लगी, लेकिन आज भी वे रोजाना नौ घंटे का वर्कआउट करते हैं। इसमें 35 किमी साइकिलिंग, 10 किमी वाक और मनुआभान टेकरी 10 बार चढ़ते उतरते हैं। इस दौरान कंधों पर करीब 20 किलो वजन होता है। दिल में एक ही सपना है कि दुनिया के सारे शिखर पर देश और प्रदेश के नाम का झंडा फहरे। वे कहते हैं कि कहने वाले करते नहीं और करने वाले कहते नहीं। मैं करने वालों में से हूं, इसलिए लक्ष्य नहीं बताऊंगा। बता दें कि 19 मई 2016 को भगवान ने एवरेस्ट फतेह किया था। उनका वाहन साइकिल है।

सरकार का खर्च कम करने पर जोर क्या पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर असर?

इस माह के आरंभ में पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकार ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और बाहरी उधारी को सीमित करने पर नए सिरे से जोर दिया। वित्त वर्ष 25 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.1 फीसदी तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है जो वित्त वर्ष 24 (संशोधित अनुमान) की तुलना में 71 आधार अंकों के समेकन को दर्शाता है। कर-जीडीपी अनुपात में भी इजाफा हुआ और यह वित्त वर्ष 24 के 10.1 फीसदी से बढ़कर वित्त वर्ष 25 (बजट अनुमान) में 11.7 फीसदी हो गया। कर-राजस्व उछाल में भी सुधार हुआ। इसके साथ ही राजस्व व्यय में नियंत्रित वृद्धि, पूंजीगत व्यय को प्रदान किए गए प्रोत्साहन के साथ मिलकर यह प्रदर्शित करती है कि उधार का एक बड़ा हिस्सा अब पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण की दिशा में निर्देशित है। उल्लेखनीय बात यह है कि राजस्व व्यय और पूंजीगत आवंटन में अनुपात में जो गिरावट आई है वह संकेत देती है कि सरकार व्यय की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास कर रही है जबकि इस दौरान वह राजकोषीय समेकन के मार्ग पर बने रहना चाहती है। इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक हालिया पत्र बेहतर ढंग से आर्थिक वृद्धि और राजकोषीय समेकन का परीक्षण करता है। दिलचस्प बात यह है कि यह पत्र पूंजीगत व्यय को नए सिरे से परिभाषित करता है और विकास संबंधी व्यय पर नजर डालता है। इसका दायरा व्यापक है क्योंकि इसमें सामाजिक और आर्थिक व्यय शामिल है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, डिजिटलीकरण और जलवायु जोखिम को भी समेटे हुए है। इसका उद्देश्य है राजस्व व्यय के उन घटकों को शामिल करना जो वास्तव में भौतिक और मानव पूंजी निर्माण के रूप में सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही पूंजीगत व्यय के उस हिस्से को अलग करना जो वृद्धि को बढ़ावा देने वाला नहीं है। वित्त वर्ष 25 में पूंजीगत व्यय के जहां जीडीपी के 3.4 फीसदी रहने का लक्ष्य तय किया गया है, वहीं विकास संबंधी व्यय के जीडीपी के 4.2 फीसदी के बराबर रहने का अनुमान है। आमतौर पर यह माना जाता है कि कम सरकारी व्यय अल्पावधि में आर्थिक वृद्धि को कमजोर करता है। परंतु राजकोषीय समेकन दीर्घावधि में वृद्धि को गति दे सकता है। ऐसा दीर्घावधि में ब्याज दरों को कम करके किया जा सकता है। इससे निजी निवेश आएगा और उसी समय अधिक उत्पादक व्यय मसलन भौतिक और मानव पूंजी में सार्वजनिक निवेश तथा लक्षित सामाजिक व्यय के लिए राजकोषीय गुंजाइश बनेगी। इस बारे में पत्र में जो उपाय सुझाए गए हैं उनमें श्रम शक्ति को नए सिरे से कौशल संपन्न बनाना, डिजिटलीकरण में निवेश करना और ऊर्जा किफायत हासिल करना शामिल है। एक वृहद आर्थिक ढांचे को नियोजित करके उक्त पत्र में कहा गया है कि विकास संबंधी वास्तविक व्यय में एक फीसदी का इजाफा संचयी गुणक प्रभाव वाला हो सकता है और चार वर्ष में जीडीपी में पांच फीसदी का इजाफा कर सकता है। उच्च श्रम उत्पादकता वाले क्षेत्रों (मसलन रसायन, वित्तीय सेवा और परिवहन आदि) में प्रशिक्षण और कौशल सहित रोजगार में एक वर्ष तक पांच फीसदी का इजाफा 2020 से 2031 तक की अवधि में जीडीपी में एक फीसदी की वृद्धि का सबब बन सकता है। इसी तरह डिजिटलीकरण और कम ऊर्जा गहनता से मध्यम अवधि में वृद्धि में इजाफा हो सकता है क्योंकि तकनीकी विकास को श्रम और पूंजी की मदद मिलेगी। अल्पावधि में दिक्रत हो सकती है। ऋण-जीडीपी अनुपात में वृद्धि के रूप में हम ऐसा देख चुके हैं लेकिन दीर्घावधि के लाभ इसकी पूर्ति कर देंगे। सरकारी व्यय को विकास संबंधी व्यय की ओर नए सिरे से संतुलित करने से 2030-31 तक आम सरकारी ऋण-जीडीपी अनुपात 73.4 फीसदी तक आ जाएगा जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा था कि मध्यम अवधि में यह जीडीपी के 100 फीसदी का आंकड़ा पर कर जाएगा अंतरिम बजट में की गयी हालिया घोषणाओं में उपरते क्षेत्रों में शोध और नवाचार के लिए एक लाख करोड़ रुपये का फंड तथा छत्तों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने की योजना ऐसे कदमों में शामिल है जो सरकारी आवंटन की गुणवत्ता सुधारने से संबंधित हैं।

भारत में घट रहे रेगिस्तान के जहाज युद्धस्तर पर संरक्षण की जरूरत

वर्ष 2012-19 के बीच हुए एक सर्वे में पता चला था कि भारत में ऊंटों की संख्या तेजी से कमी आई है। देश में यह डेढ़ लाख घटकर 2.52 लाख हो रह गए थे। वर्ष 2019-23 के बीच यह संख्या और घटी है। नागालैंड और मेघालय जैसे राज्यों में तो अधिकारिक रूप से ऊंट समाप्त हो चुके हैं। ऊंट का जिक्र आते ही रेगिस्तान का ख्याल एकाएक मन में आ जाता है। एक समय रेगिस्तान में यातायात का मुख्य साधन रहा ऊंट अब संकट में है। इनकी संख्या न केवल भारत में, बल्कि दुनिया में घट रही है। शायद यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को ऊंट वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, ताकि लोगों का ध्यान ऊंट के संरक्षण की तरफ भी जाए। दुनिया के 90 देशों में ऊंटों के संरक्षण और इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। भारत में राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं और यहीं पर पिछले कुछ सालों में सरकारी स्तर पर कुछ कार्य हुए हैं। खासकर वर्ष 2014 में राजस्थान सरकार ने ऊंट को राज्य पशु घोषित किया था और वर्ष 2015 में राज्य सरकार राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रजनन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम लेकर आई, इसके तहत ऊंट के राज्य से बाहर निर्यात पर पाबंदी लगी। हालांकि, बाद में एक सक्षम प्राधिकार को ऊंटों के राज्य से बाहर निर्यात के लिए परमिट जारी करने का अधिकार दे दिया गया। सच्चाई यह है कि परमिट पाना आसान प्रक्रिया नहीं है और इसमें लंबा समय लगता है।



उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया के ऊंटों को असली ऊंट माना जाता है। इनमें झोमेड्री (एक कूबड़ वाला ऊंट) और बैक्ट्रियन (दो कूबड़ वाला ऊंट) हैं। भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा में मुख्य रूप से ऊंट पाए जाते हैं, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक 2.14 लाख ऊंट हैं, जबकि देश भर में इनकी संख्या 2.50 लाख से कम हो गई है। वर्ष 2012-19 के बीच हुए एक सर्वे में पता चला था कि भारत में ऊंटों की संख्या तेजी से कमी आई है। देश में यह डेढ़ लाख घटकर 2.52 लाख हो रह गए थे। वर्ष 2019-23 के बीच यह संख्या और घटी है। नागालैंड और मेघालय जैसे राज्यों में तो अधिकारिक रूप से ऊंट समाप्त हो चुके हैं। राजस्थान में ऊंट की गोमट, नांचना, जैसलमेरी, मेवाड़ी, अलवरी, सिंधी, कच्छी और बीकानेरी प्रजाति पाई जाती हैं। राजस्थान के लोकदेवता पाबूजी को ऊंटों का देवता कहते हैं।

गुजरात में तो समुद्र में तैरने वाले ऊंट भी मिलते हैं। यह कच्छ की खराई किस्म के ऊंट हैं। जो हर रोज समुद्र में विचरण करते हैं और समुद्री वनस्पति मेंरूबूब को खाते हैं। हालांकि, पिछले कुछ सालों में उद्योगों के विस्तार के कारण मेंरूबूब खत्म हो रहे हैं और खराई ऊंटों के लिए खाने की समस्या आ रही है। अब पूरे गुजरात में 4500 हजार से आसपास खराई ऊंट ही बचे हैं। ऊंटों को संरक्षण देने के कई प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1984 में बीकानेर में उष्ट परियोजना निर्देशालय की स्थापना की थी। वर्ष 1995 में इसे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र में तब्दील कर दिया गया। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023 में उष्ट संरक्षण योजना के तहत टोडियाँ (ऊंट के बच्चे) के जन्म पर दो किशतों में 10 हजार रुपए ऊंट पालक को बतौर प्रोत्साहन राशि देने प्राप्रंभ किया था। रेगिस्तान के जहाज की संख्या घटना वाकई चिंताजनक है।

चंद्र ग्रहण के साए में होली, जानिए त्योहार पर क्या होगा इसका प्रभाव



होली पर चंद्र ग्रहण का साया

इस साल होली का त्योहार 25 मार्च को है, लेकिन इस बार होली के रंग में भंग पड़ने वाली है, क्योंकि इसी दिन साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। फाल्गुन माह

में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल होली का त्योहार 25 मार्च को है, लेकिन इस बार होली के रंग में भंग पड़ने वाली है, क्योंकि इसी दिन साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। वैसे तो ग्रहण एकमात्र खगोलीय घटना है, लेकिन इसे धार्मिक शास्त्रों में शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान कई प्रकार

की नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिसका प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ता है, इसलिए इस साल होली पर चंद्र ग्रहण का लगना शुभ नहीं माना जा रहा है। ऐसे में चलिए जानते हैं 25 मार्च को होली वाले दिन चंद्र ग्रहण कब लगेगा और रंगों के त्योहार पर इसका क्या प्रभाव होगा... हिंदी पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण सुबह 10 बजकर 23 मिनट से शुरू होगा, जो दोपहर 03 बजकर 02 मिनट तक रहेगा।

अभिप्राय/धर्म/संस्था

पड़ोस : पाकिस्तान में कुछ भी संभव है, क्योंकि सेना की मर्जी पर आई और गई है हर सरकार



पाकिस्तान में उलझा सत्ता का गणित...

गठबंधन सरकार बनाने पर कोई फैसला कर पाए और न ही सहमत हो पाए। कराची शेयर बाजार गिरने लगा और कार्यवाहक सरकार के मुताबिक बजट घाटा बढ़कर 85.4 खरब डॉलर तक पहुंच गया। सुधारों और महत्वपूर्ण विदेशी फंडिंग में देरी के कारण बने गतिरोध ने अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड की बिकवाली को बढ़ावा दिया और मुल्क में आर्थिक संकट के और अधिक बढ़ने की विश्लेषकों की आशंका को बल मिला। घटती विदेशी मुद्रा के साथ पाकिस्तान आर्थिक संकट में था, अगले दो महीनों में एक अरब बॉन्ड भुगतान के कारण उस पर और दबाव बढ़ेगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ उसका तीन अरब डॉलर का फंडिंग कार्यक्रम 12 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। वित्त मंत्रालय के पूर्व सलाहकार और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के साजिद अमीन ने कहा कि यदि कोई भी पार्टी सामान्य बहुमत नहीं जुटा पाती है, तो पाकिस्तान गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकट के दौर में प्रवेश कर जाएगा। यह संकट इतना गहरा गया कि आर्थिक पतन से चिंतित सुरक्षा प्रतिष्ठान ने पीपीपी और पीएमएल-एन को

एक सख्त संदेश भेजा कि बस बहुत हो चुका, अगर छह दौर की वार्ता के बाद भी वे सरकार की घोषणा नहीं कर पाए, तो वे उनके लिए फैसले लेंगे। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि सुरक्षा प्रतिष्ठान ने जेल में इमरान खान से बात करने के लिए भी एक मध्यस्थ भेजा कि वह नौ मई, 2023 की तबाही और फौजी प्रतिष्ठानों पर हमले में अपनी भूमिका कबूल कर लें, तो अपने निर्दलीय उम्मीदवारों को सत्ता में शामिल कर सकेंगे और उन्हें इस्लामाबाद स्थित उनके आवास बनिगाला ले जाया जाएगा, जिसे फिलहाल एक उप-जेल में तब्दील कर दिया गया है और जहां उनकी पत्नी बुशरा बीबी को रखा गया है। लेकिन इमरान खान ने अपने प्रसिद्ध दो शब्दों में जवाब दिया-बिल्कुल नहीं। जाहिर है कि पाकिस्तान के इतिहास में सबसे विवादास्पद चुनाव में धांधली करने वाला सुरक्षा प्रतिष्ठान अब हाथ मल रहा है। सुरक्षा प्रतिष्ठान के करीबी माने जाने वाले सीनेटर मुशाहिद हुसैन (पीएमएल-एन) ने मानो सेना के संकेत पर सीनेट में बिल्कुल सटीक कहा कि यदि पीएमएल-एन, पीपीपी और पीटीआई मिलकर कोई फैसला

नहीं लेते हैं, तो सैन्य मुख्यालय फैसला करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा स्थिति में सबसे बड़ी जिम्मेदारी नवाज शरीफ की है। पीपीपी के आसिफ अली जरदारी और पीएमएल-एन के शहबाज शरीफ को जैसे ही सेना का संदेश मिला, आधी रात में जल्दबाजी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की कि अब उनके पास बहुमत साबित करने के लिए जाडुई आंकड़ा है और वे गठबंधन सरकार बनाएंगे। शहबाज शरीफ सदन के भावी नेता होंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति होंगे। जरदारी यह पद पीपीपी सरकार के दौरान पहले भी संभाल चुके हैं। गठबंधन सरकार की घोषणा के बाद बुधवार सुबह में शेयर बाजार में 1,000 से ज्यादा अंकों की बढ़ोतरी हुई। विश्लेषकों ने इस बढ़त का श्रेय सरकार गठन पर आम सहमति को दिया। नई गठबंधन सरकार का नाम पीडीएम-2.0 रखा गया है। यह वही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सरकार है, जिसने अविश्वास प्रस्ताव से इमरान के हटने के बाद करीब एक साल तक शासन किया और जिसे आम नागरिकों के लिए सबसे खराब सरकार के रूप में

याद किया जाता है। नवाज शरीफ के लिए परेशानी की बात यह है कि पीपीपी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने से इन्कार कर दिया है, पर पंजाब में राज्यपाल एवं मंत्री पद की मांग की है। पीपीपी का कहना है कि वह सदन के नेता के रूप में शाहबाज शरीफ के लिए वोट करेगी और नेशनल असेंबली में मुद्दे के आधार पर समर्थन भी करेगी, लेकिन संघीय सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। पंजाब में पीएमएल-एन ने निर्दलीय और पीपीपी की मदद से बहुमत जुटा लिया है और नवाज शरीफ ने घोषणा की है कि उनकी बेटी और राजनीतिक उत्तराधिकारी पंजाब की मुख्यमंत्री होंगी। इस तरह पंजाब के इतिहास में पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री होंगी। इस बीच पीटीआई ने उदारवादी इस्लामी पार्टी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है, क्योंकि सुरक्षा प्रतिष्ठान ने पीटीआई को अपने चुनाव चिह्न 'बल्ले' का उपयोग करने से वंचित कर दिया था, इसलिए उसके उम्मीदवारों को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। वे निचले सदन में पीपीपी के साथ विपक्ष की सीट पर बैठेंगे, जिससे यह संसदीय इतिहास में सबसे मजबूत विपक्ष बन जाएगा, जो सरकार के हर कदम को रोकने की ताकत भी रखेगा। राजनीति संभावनाओं की कला है और कौन जानता है कि सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक इशारे पर कल क्या होगा, क्योंकि संयुक्त विपक्ष के पास कमजोर शहबाज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीडीएम-2.0 रखा गया है। ब्रिटिश इंडिया से आजाद होने के बाद 1970 में पहली बार पाकिस्तान में प्रत्यक्ष आम चुनाव हुए थे। लेकिन 2024 के आम चुनाव ने दिखा दिया कि इसका सबसे बड़ा शिकार जम्हूरियत है।

पर्यावरण : संकटग्रस्त दुनिया को नई चेतावनी, आखिर किस बड़ी मुसीबत की ओर इशारा कर रही है डूम्सडे क्लॉक

धरती की जीवनदायिनी क्षमताओं के अधिक संकटग्रस्त होने के बीच हाल ही में वैज्ञानिकों ने नई चेतावनी जारी की है। इसे डूमस्डे क्लाक चेतावनी कहा जा रहा है। विश्व में ‘डूमस्डे क्लॉक’ अपनी तरह की एक प्रतीकात्मक घड़ी है, जिसकी सुइयों की स्थिति के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया जाता है कि विश्व किसी बहुत बड़े संकट की आशंका के कितने नजदीक है। इस घड़ी का संचालन ‘बुलेटिन ऑफ एटोमिक साइंटिस्ट्स’ नामक वैज्ञानिक संस्थान द्वारा किया जाता है। इसके परामर्शदाताओं में 15 नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। ये सभी मिलकर प्रति वर्ष तय करते हैं कि इस वर्ष घड़ी की सुइयों को कहाँ रखा जाए। इस घड़ी में रात के 12 बजे को धरती पर बहुत बड़े संकट का पर्याय माना गया है। घड़ी की सुइयाँ रात के 12 बजे के जितने नजदीक रखी जाएंगी, उतने ही बड़े संकट से धरती (व उसके लोगों व जीवों) के संकट की स्थिति मानी जाएगी। 2024 में इन सुइयों को (रात के) 12 बजे में 90 सेकंड पर रखा गया है। संकट के प्रतीक 12 बजे के समय से इन सुइयों की इतनी नजदीकी 2023-24 के अतिरिक्त कभी नहीं रही। दूसरे शब्दों में, यह घड़ी दर्शा रही है कि इस समय धरती किसी बहुत बड़े संकट के सबसे करीब है। ‘डूमस्डे घड़ी’ के वार्षिक प्रतिवेदन में इस स्थिति के तीन कारण बताए गए हैं। पहली वजह यह है कि जलवायु बदलाव का संकट बढ़ रहा है। जलवायु बदलाव नियंत्रित करने की संभावनाएं समग्र रूप से धूमिल हुई हैं। दूसरी वजह यह है कि परमाणु हथियार नियंत्रित करने के समझौते कमजोर हुए हैं, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा है। तीसरी वजह यह है कि ए.आई. (आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस) व जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, जिसका सुरक्षा पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इन तीन कारणों के मिले-जुले असर से आज विश्व बहुत बड़े संकट की आशंका की दहलीज पर पहुंच चुका है। और इस संकट को कम करने के लिए तुरंत कदम



उठाना जरूरी है। सवाल यह है कि क्या ‘डूमस्डे घड़ी’ के इस अति महत्वपूर्ण संदेश को विश्व टिपिंग पॉइंट भी जुड़े हैं। एक बार यह सीमा पार हो गई, तो फिर स्थिति अनियंत्रण से बाहर निकल सकती हैं। विश्व के शीर्ष विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास बस एक दशक बचा है। एक बड़ी जरूरत इस बात की है कि धरती के जीवन पर मंडरा रहे अभूतपूर्व संकट की समझ अधिक लोगों तक पहुंचे। यह समझ सही परिप्रेक्ष्य में अधिक लोगों तक पहुंचेगी, तभी लोग अधिक संख्या में आगे आएंगे। इस समय इन मुद्दों की गंभीरता की जानकारी रखने वाले लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इन मुद्दों को न्याय व लोकतंत्र के मुद्दों से जोड़कर व्यापक समझ बनानेवाले लोगों की संख्या तो और भी कम है। ऐसी समझ बनाकर हमें धरती की रक्षा की वह राह निकालनी है, जो समता व सादगी, न्याय व लोकतंत्र की राह है। इस समय संकट और समाधान की सही समझ को अधिक लोगों तक पहुंचाना और उन्हें समाधान के प्रयासों से जोड़ना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

फलों के रस से अभिषेक के बाद अखरोट और चेरी से हुआ महाकाल का श्रृंगार, चांदी की मुण्डमाला धारण की



भस्म आरती में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के जयघोष के साथ महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर शुक्रवार तड़के भस्म आरती के दौरान मंदिर के पट खुलते ही पण्डे पुजारी ने गर्भगृह में स्थापित सही भगवान की प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान महाकाल का जलाभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से बने पंचामृत से कर पूजन-अर्चन किया। इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरि ओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद बाबा महाकाल को रजत का मुकुट और चन्द्र धारण करवाया गया। आज बाबा महाकाल का मावे से श्रृंगार कर उन्हें अखरोट और चेरी से सजाया गया। इसके बाद बाबा महाकाल के ज्योतिर्लिंग को कपड़े से ढंककर भस्मी रमाई गई। भस्म अर्पित करने के पश्चात भगवान महाकाल को चांदी की मुण्डमाल और रुद्राक्ष माला के साथ सुगंधित पुष्पों की माला अर्पित कर फल और मिष्ठान का भोग लगाया गया। भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे जिन्होंने बाबा महाकाल के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य दर्शनों का लाभ लिया।

अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में गिरावट आने से भारतीय बाजार भी प्रभावित रहा

इंदौर सराफा बाजार सहित रतलाम व उज्जैन में क्या है सोने-चांदी के भाव जाने यहां

चांदी में ऊंचे दामों पर ग्राहकी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में गिरावट आने से भारतीय बाजार भी प्रभावित रहा। कामेक्स पर चांदी वायदा 5 सेंट घटकर 23.12 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। गुरुवार को इंदौर में चांदी चौरसा 100 रुपये घटकर 72200 रुपये प्रति किलो रह गई। दूसरी ओर कामेक्स पर सोना वायदा आंशिक सुधरकर 2034 डालर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया।इधर, भारतीय बाजारों में वैवाहिक सीजन के मुहूर्त 10 मार्च तक खूब होने के कारण सराफा बाजार में गहनों में ग्राहकी एक बार फिर बढ़ने लगी है। इसके चलते इंदौर में सोना केडबरी के दाम धीमी गति से बढ़ रहे हैं। गुरुवार को सोना केडबरी सुधरकर 63650 रुपये प्रति दस



पर पहुंच गया। गुरुवार को एशियाई व्यापार में सोने की कीमतें थोड़ी बढ़ी, लेकिन काफी हद तक हालिया ट्रेडिंग रेंज के भीतर वहीं क्योंकि फेडरल रिजर्व के कई संकेतों ने अमेरिकी ब्याज दरों में लंबे समय तक बढ़ोतरी की संभावना दोहराई है। कामेक्स सोना ऊपर में 2034 नीचे में 2025 डालर प्रति औंस और चांदी ऊपर में 23.12 नीचे में 22.85 डालर

प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया। सोना केडबरी रवा नकद में 63650 सोना (आरटीजीएस) 63875 सोना (91.60 कैरेट) 58510 रुपये प्रति दस ग्राम बोला गया। गुरुवार को सोना 63625 रुपये पर बंद हुआ था। चांदी चौरसा 72200 चांदी टंच 72300 चांदी चौरसा (आरटीजीएस) 72100 रुपये प्रति किलो बोली गई। गुरुवार को चांदी 72300 रुपये पर बंद हुई थी।

ओपन बुक परीक्षा को लेकर सीबीएसई की कवायद, चयनित स्कूलों में होगा ट्रायल

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड(सीबीएसई) 2024 के अंत में कक्षा 9 से 12 तक के लिए ओपन बुक परीक्षा(ओबीई) के पायलट कार्यक्रम की योजना बना रहा है, शुरुआत में यह सिर्फ चयनित स्कूलों में ही की जाएगी। गौरतलब है कि 2023 में बोर्ड की आखिरी गवर्निंग बॉडी मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि सीबीएसई के अधिकारियों ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में इसे लागू करने की योजना से इंकार किया है। ओपन-बुक परीक्षा में छात्रों को परीक्षा के दौरान अपने नोट्स, पाठ्यपुस्तकें या अन्य अध्ययन सामग्री ले जाने अर्थात् उन्हें देखने की अनुमति होती है। सीबीएसई चयनित स्कूलों में ओपन बुक परीक्षा मूल्यांकन के एक पायलट कार्यक्रम पर विचार कर रहा है। जिसमें कक्षा नौ और 10 के लिए अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों को लक्षित किया गया है। वहीं कक्षा 11 और 12 के लिए अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान विषयों को योजना का हिस्सा बनाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक सटीक मूल्यांकन करना है। इन परीक्षाओं को पूरान करने और फीडबैक इकट्ठा करने में छात्रों को लगने वाले समय को बारीकी से समझा जाएगा।

साल के अंत तक चयनित स्कूलों में होगा पायलट कार्यक्रम ओपन बुक परीक्षा के पायलट

कार्यक्रम पर बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह योजना राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में की गई सिफारिशों के अनुरूप है। इसके जरिए हम मूल्यांकन करेंगे। इन परीक्षाओं को पूरा करने तक का समय, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। चयनित स्कूलों को एक पायलट कार्यक्रम से गुजरना पड़ेगा। पायलट कार्यक्रम का फोकस उच्च-स्तरीय मानसिक कौशल, अनुप्रयोग, विश्लेषण, आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच और समस्या सुलझाने की क्षमताओं का आकलन करने पर केंद्रित होगा। ओपन बुक टेस्ट का डिजाइन, विकास और समीक्षा जून 2024 तक पूरा करने का प्रस्ताव है, स्कूलों में सामग्रियों के पायलट परीक्षण की योजना नवंबर-दिसंबर 2024 में बनाई जा रही है। गौरतलब है कि सीबीएसई ने पहले 2014-15 से 2016-17 तक तीन वर्षों के लिए कक्षा 9 और 11 की वर्ष के अंत की परीक्षाओं के लिए एक ओपन टेक्स्ट आधारित मूल्यांकन (ओटीबीए) प्रारूप का इस्तेमाल किया था, लेकिन नकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। बैठक में बोर्ड ने ओबीई प्रश्नों में कई उत्तरों की क्षमता को समझने के लिए शिक्षकों को पहले ओपन बुक परीक्षा देने पर भी विचार किया।

तुवर में मिल वालों की मांग से तेजी आयातकों की बिक्री से मसूर में नरमी

तुवर की आवक फिर कम होने और मिलर्स की मांग मंडियों में आने के कारण भाव में 100 रुपये की तेजी देखी गई। गुरुवार को तुवर महाराष्ट्र सफेद बढ़कर 10100-10300 कर्नाटक 10300-10500 निमाड़ी तुवर 8700-9600 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। दरअसल, तुवर दाल में सीमित रूप से उपभोक्ता पूछताछ बाजार में अच्छी आने से मिलर्स की तुवर में खरीद बढ़ी है। मिलर्स भी मिलों में तुवर दाल का स्टॉक हलका होने पर ही खरीदारी के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं क्योंकि सरकार दालों की तेजी पर नजर बनाए हुए हैं। दूसरी ओर मसूर में अपेक्षित ग्राहकी नहीं होने और आयातित मालों की आवक के कारण कीमतें दब रही हैं। गुरुवार को मसूर मे करीब 50-75 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। मंडी में मसूर घटकर 5825-5850 रुपये प्रति क्विंटल रह गई। घरेलू फसल मध्यप्रदेश, राजस्थान में तैयार हो चुकी है और कटाई भी शुरू हो गई है।



इधर, यूपी की फसल अगले महीने आएगी। अतः वर्तमान भाव पर लंबी तेजी की गुंजाइश नहीं है। आयातक मुंदड़ा बंदरगाह पर मसूर के दाम ऊंचे बोल रहे थे लेकिन लेवाल कम होने से पुनः दाम घटाकर बिकवाली कर रहे हैं। घरेलू मसूर का उत्पादन 17-18 लाख टन होने का अनुमान है, जो गत वर्ष की अपेक्षा काफी अधिक है। काबुली चने में निर्यातकों की सीमित पूछपरख बनी हुई है

जबकि नए मालों की आवक जैसी होना चाहिए वैसी नहीं होने से काबुली चने के दाम मजबूती पर टिके हुए हैं। देसी चने में भी मांग अच्छी रहने से भाव स्थिर रहे। अन्य दाल-दलहन में कारोबार सामान्य रहा। भाव में कोई खास परिवर्तन नहीं रहा। दलहन- चना कांटा 6000-6050 विशाल 5800-5900 नया विशाल 5600-5800 डंकी 5500-5700 मसूर 5825-5850 तुवर महाराष्ट्र सफेद 10100-

10300 कर्नाटक 10300-10500 निमाड़ी तुवर 8700-9600 मूंग 9000-9100 बारिश का मूंग नया 9200-10000 एवरेज 7000-8000 उड़द बेस्ट 8800-9200 मीडियम 7000-8000 हलका उड़द 3000-5000 नया गेहूं मिल क्वालिटी 2100-2450 मालवराज बेस्ट 2250-2300 लोकवन 2650-2900 पूर्णा 2600-2845 रुपये क्विंटल के भाव रहे। दालों के दाम- चना दाल

7800-7900 मीडियम 8000-8100 बेस्ट 8200-8300 मसूर दाल 7400-7500 बेस्ट 7600-7700 मूंग दाल 10700-10700 बेस्ट 10800-10900 मूंग मोगर 11200-11300 बेस्ट 11400-11500 तुवर दाल 11800-12000 मीडियम 12900-13000 बेस्ट 13900-14000 ए. बेस्ट 14900- 15000 पैकड तुवर दाल नई 15000 उड़द दाल 10800-10900 बेस्ट 11000-11100 उड़द मोगर 11000-11100 बेस्ट 11200-11300 रु. क्विंटल । इंदौर चावल भाव- दयालदास अजीतकुमार छावनी के अनुसार बासमती (921) 11500-12500, तिवार 10000-11000, बासमती दुबार पोनिया 8500-9500, मिनी दुबार 7500-8500, मोगरा 4500-7000, बासमती सेला 7000-9500 कालीमूँछ डिनरकिंग 8500, राजभोग 7500, दुबराज 4500-5000, परमल 3200-3400, हंसा सेला 3400-3600, हंसा सफेद 2800-3000, पोहा 4300-4700 रु. क्विंटल।

टेस्ट करियर के दूसरे ओवर में ही बल्लेबाज को किया वलीन बोल्ड लेकिन बदकिस्मत रहे आकाश दीप



भारत और इंग्लैंड के बीच रांची टेस्ट में आकाश दीप का पदार्पण हुआ। टीम इंडिया में जसप्रीत बुमराह के स्थान पर उनको स्थान मिला है। आकाश दीप के करियर की शुरुआत नाटकीय रही। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद सिराज ने की। पारी का दूसरा ओवर आकाश दीप को मिला। उन्होंने प्रभावी गेंदबाजी की। आकाश दीप के दूसरे और इंग्लैंड की पारी के चौथे ओवर में जो कुछ हुआ, उसकी चर्चा हर क्रिकेट प्रेमी कर रहा है। दरअसल, उस ओवर की दूसरी गेंद पर आकाश दीप ने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज क्रॉली का ऑफ स्टम्प उखाड़ दिया। पूरी टीम खुशी से झूम उठी। आकाश दीप को भी लगा कि यह उनके टेस्ट करियर की शानदार शुरुआत है, लेकिन बाद में वह गेंद नोबॉल निकली।

भारत-रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), आर अश्विन, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप

इंग्लैंड-जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स (कप्तान), बेन फॉक्स (विकेटकीपर), रेहान अहमद, टॉम हार्टले, शोएब बशीर, ओली रॉबिन्सन

सऊदी जाने वाले भारतीय पर्यटकों को अब 96 घंटे का मुफ्त वीजा, पांच साल के लिए भी खास ऑफर

दुबई । सऊदी अरब जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। राजधानी रियाद का लक्ष्य 2030 तक 7.5 मिलियन भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करना है। सऊदी के स्थापना दिवस पर शोष अधिकारी ने कहा कि पिछले साल सऊदी अरब आने वाले भारतीयों की संख्या में 50 प्रतिशत उछाल दर्ज किया गया। सऊदी आने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए 96 घंटे का मुफ्त वीजा योजना का जिक्र करते हुए अलहसन अल्दाबाग ने कहा, स्टॉप ओवर कार्यक्रम के तहत सऊदी आने पर 96 घंटे के लिए मुफ्त वीजा दिया जाएगा। इसका लाभ सऊदी एयरलाइंस या फ्लाईनास (एक निजी सऊदी कम लागत वाली एयरलाइन) से यात्रा करने पर मिलेगा। अल्दाबाग सऊदी पर्यटन प्राधिकरण में अध्यक्ष हैं। वे एशिया-प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख हैं। सऊदी अब में भारतीय बाजार की भूमिका पर अल्दाबाग ने जोर देकर कहा, भारत सऊदी के लिए एक प्राथमिकता वाला बाजार है। पिछले साल भारत से 1.5 मिलियन आगंतुक सऊदी आए।



50 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए अगले छह साल में (2030 तक) भारत से सऊदी अरब में आने वाले आगंतुकों की संख्या 7.5 मिलियन तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

दुबई जाने वाले लोगों के



लिए भी खास ऑफर सऊदी के अलावा दुबई ने भी भारत से आने वाले लोगों के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने की पहल की है। दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म (डीईटी) के मुताबिक दुबई ने भारत और खाड़ी देश के बीच

यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पांच साल की वैलिडिटी के साथ बहु-प्रवेश वीजा की पेशकश की है। 2018 में भारत से 1.84 मिलियन पर्यटक दुबई गए थे। 2019 में संख्या बढ़कर 1.97 मिलियन हो गई। 2023 में 2.46 मिलियन आगंतुक भारत से दुबई पहुंचे।

डीईटी के मुताबिक आगंतुकों के आंकड़ों से पता चलता है कि साल-दर-साल 34 प्रतिशत की असाधारण वृद्धि हुई है। भारत से सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों दुबई आ रहे हैं। इसे देखते हुए दुबई ने भारत और दुबई के बीच यात्रा को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। निरंतर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और पर्यटन और व्यापार संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए पांच साल का बहु-प्रवेश वीजा देने का फैसला लिया गया है। वीजा 2-5 कार्यदिवसों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। इस वीजा के आधार पर वीजा-पासपोर्ट धारक 90 दिनों तक दुबई में रुक सकता है। प्रवास की पूरी अवधि को अधिकतम 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। डीईटी के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में दुबई में कुल 17.15 मिलियन अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आए। 2022 में 14.36 मिलियन पर्यटकों ने दुबई में दस्तक दी। कुल आगमन के मामले में 19.4 प्रतिशत वृद्धि देखते हुए अब वीजा निर्गत करने की अधिक सुगम प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

गाजा में इजराइली हमलों में कम से कम 48 लोगों की मौत

मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल

इंटरनेशनल डेस्क: दक्षिणी और मध्य गाजा में रात भर चले इजराइली हमलों में कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई, जिनमें आधी संख्या महिलाओं और बच्चों की है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। वहीं, यूरोपीय विदेश मंत्रियों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने मानवीय संकट व क्षेत्र में भुखमरी की आशंका पर बढ़ती चिंताओं के बीच संघर्षविराम का आह्वान किया। इजराइली पुलिस ने बताया कि इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी तनाव बढ़ रहा है, जहां बृहस्पतिवार सुबह तीन फलस्तीनी बंदूकधारियों ने राजमार्ग पर एक जांच चौकी से गुजर रहे वाहनों पर



गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच अन्य लोग घायल हो गए। इस संबंध में एक इजराइली अधिकारी ने बुधवार देर रात बताया कि

इजराइल और हमास के बीच संघर्षविराम समझौते को लेकर नए प्रयास जारी हैं। अधिकारी ने कहा कि समझौता ही गाजा में युद्ध को रोक सकता है और दक्षिणी

इजराइल पर सात अक्टूबर को हुए हमले के बाद से चरमपंथियों द्वारा बंधक बनाए गए लगभग 130 इजराइली बंधकों को रिहा कराने में मदद कर सकता है। लगभग एक सप्ताह पहले समझौते को लेकर जारी बातचीत रुक गई थी लेकिन इजराइल की ओर से यह बयान संघर्षविराम की एक नई उम्मीद लेकर आया है। वहीं, पूर्व सैन्य प्रमुख और रक्षा मंत्री बेनी गेंट्ज ने अपना संकल्प दोहराते हुए कहा कि अगर हमास शेष बंधकों को रिहा नहीं करेगा तो इजराइल 10 मार्च के आसपास शुरु होने वाले रमजान महीने के दौरान गाजा के दक्षिणी शहर रफह पर जमीनी हमला करेगा।

आज से झारखंड विधानसभा के सत्र की शुरुआत, 27 फरवरी को सदन में पेश होगा बजट

झारखंड विधानसभा में आज यानी शुक्रवार से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 23 फरवरी से 2 मार्च तक यह सत्र चलेगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में 27 फरवरी को सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण से होगी। वहीं, बीते गुरुवार को इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सत्र को शांति रूप से संचालन करने के मुद्दों पर बात की गई। सरकार की ओर से यह उम्मीद जताई जा रही है कि चंपई सोरेन की सरकार का यह बजट सत्र झारखंड के लोगों के लिए काफी कल्याणकारी साबित होगी। सरकार सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार है विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए सभी दलों के विधायकों से अपील किया। वहीं छोटे बजट सत्र को लेकर भाजपा ने नाराजगी जताई है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने साफ कहा है कि झारखंड जैसे प्रदेश में 6 कार्य दिवस जैसे बजट सत्र बुलाना झारखंडवासियों के भावना के साथ खिलवाड़ है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार है और इस बार का बजट भी झारखंड की जनता के हित में होगा। बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे हेमंत सोरेन उधर, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली है। ईडी की विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें जेल में ही रहना होगा। बजट सत्र के दौरान उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बता दें कि बजट सत्र में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हेमंत सोरेन ने कोर्ट से बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी गई थी। इस फैसले पर बीते बुधवार को कोर्ट में दोनों ही पक्षों के द्वारा बहस किया गया, जहां हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अपनी दलील रखी तो वहीं ईडी की तरफ से दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील जुड़े थे। हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब किसी ज्यूडिशियल कस्टडी में रहे इंसान को सत्र में अनुमति मांगी जा रही है। महाधिवक्ता ने कोर्ट में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो और जेएमएम विधायक नलिन सोरेन का हवाला दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वित्तीय बिल पेश होना है, इसलिए हेमंत सोरेन का उपस्थित होना अनिवार्य है। ईडी की ओर से बहस करते हुए ऑनलाइन जुड़े वकील ने कहा कि वया कोई इंसान अगर ज्यूडिशियल कस्टडी में होगा और वह ड्यूटी जाने की अनुमति कोर्ट से मांगेगा, तो वया कोर्ट से अनुमति देगी अगर नहीं तो इन्हें भी जाने का हक नहीं बनता और ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं हैं। जांच एजेंसी ईडी ने मुख?यमंत्री की अर्जी का कोर्ट में विरोध किया था कि अगर हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं तो सबूतों को नष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं, ईडी की बात को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री की मांग को खारिज कर दिया।

अमेरिका में फोन सेवा ठप, कंपनी ने सामने आकर दी सफाई

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका में कई जगहों पर सेलुलर बंद होने की शिकायत मिली है। जानकारी के मुताबिक, अमेरिकी नेटवर्क कंपनी एटी एंड टी क्रिकेट वायरलेस, वेरिजोन, टी-मोबाइल और अन्य सेवा प्रदाताओं पर सेलुलर आउटेज से से परेशान हैं। ह्यूस्टन, अटलांटा और शिकागो सहित कई स्थानों पर एटी एंड टी में सुबह 9३0 बजे ईटी के आसपास 73,000 से अधिक घरों में बिजली कटौती हुई। कटौती लगभग 3३0 बजे ईटी से शुरू हुई। वाहक के 240 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं, जो देश का सबसे बड़ा है। कंपनी ने बयान जारी कर बताया है कि हमारे कुछ ग्राहक आज



सुबह वायरलेस सेवा में रुकावट का अनुभव कर रहे हैं। हम उन्हें सेवा बहाल करने के लिए तत्काल काम कर रहे हैं।

एटीएंडटी ने एक बयान में कहा, हम सेवा बहाल होने तक वाई-फाई कॉलिंग के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करते हैं।

वेनेजुएला में सोने की गैरकानूनी खदान में हादसा, 23 मजदूरों की मौत

इंटरनेशनल डेस्क: वेनेजुएला में अवैध रूप से संचालित सोने की खदान के दहने से कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। कुछ अन्य अधिकारियों के अनुसार खदान में बड़ी संख्या में लोग फंसे हो सकते हैं। बोलिवर राज्य के गवर्नर एंजेल मार्कानो ने स्थानीय संवाददाताओं से कहा कि अब तक 14 शव निकाले जा चुके हैं और अधिकारियों को कम से कम 11 लोगों के घायल होने की जानकारी है। 5अब तक 23 मजदूरों की मौत वेनेजुएला के बोलिवर प्रांत के जंगलों में स्थित सोने की गैरकानूनी बुल्ला लोका खदान के दहने से हुए हादसे में अब तक 23 मजदूरों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इन लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई



जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार जिस समय खदान में हादसा हुआ था उस समय करीब 200 मजदूर खदान में थे। कई लोग घायल

वेनेजुएला की खदान में हुए इस हादसे में कई मजदूर घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अमेरिकी राजनयिक रिचर्ड ने अमेरिका-भारत रक्षा संबंधों को बताया अद्वितीय, पन्डू को लेकर कही बड़ी बात

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका के प्रबंधन और संसाधन राज्य उप सचिव रिचर्ड आर वर्मा ने अमेरिका और भारत के बीच रक्षा साझेदारी की असाधारण प्रकृति की सराहना की, और कहा कि यह इस दुनिया में किसी भी अन्य देश से अलग है। एक साक्षात्कार में वर्मा ने दोनों देशों द्वारा आयोजित मजबूत और प्रेरणादायक संयुक्त रक्षा अभ्यासों के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की, और हर स्तर पर उनकी परिष्कार पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत प्रमुख रक्षा साझेदार हैं, ऐसी स्थिति जो दुनिया के किसी अन्य देश के साथ हमारी नहीं है। हम इस अविश्वसनीय मजबूत रक्षा संबंध की निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं उन रक्षा अभ्यासों को देखता हूँ जो हमारी दोनों सेनाएं एक साथ करती हैं, तो यह बहुत उत्साहजनक होता



है। यह बहुत प्रेरणादायक है, यह हर स्तर पर बहुत शानदार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ भारत सबसे अधिक सैन्य अभ्यास करता है, जो पैमाने और जटिलता में बढ़ रहा है। इन महत्वपूर्ण द्विपक्षीय अभ्यासों में युद्ध अभ्यास (सेना), वज्र प्रहार (विशेष बल), मालाबार (नौसेना), कोप इंडिया

(वायु सेना), और टाइगर ट्रायम्फ (त्रि-सेवाएं) शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार रेड फ्लैग, रिमपैक, कटलैस एक्सप्रेस, सी ड्रैगन और मिलान कुछ बहुपक्षीय अभ्यास हैं जिनमें दोनों देश भाग लेते हैं। वर्मा ने पिछले दो दशकों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को स्वीकार करते हुए महत्वपूर्ण रक्षा

देर रात अचानक बनारस की सड़कों पर निकले पड़े मोदी योगी भी दिखे साथ...लोगों ने छतों से किया अभिवादन

वाराणसी- काशी को करोड़ों रुपए की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच चुके हैं। पीएम के दौरे का आज दूसरा दिन है। बनारस पहुंचते ही पीएम मोदी आधी रात को ही निरीक्षण करने सड़क पर निकल पड़े। इस दौरान उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने रात के समय शिवपुर-फुलवरिया-लहरतारा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने इसकी तस्वीरें भी शेरार की हैं, जिसमें उनके साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और सुरक्षार्कर्म भी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने टवीट कर लिखा, काशी में आकर शिवपुर-फुलवरिया-लहरतारा मार्ग का निरीक्षण किया। इस परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया गया था और यह शहर के दक्षिणी हिस्से के लोगों के लिए काफी मददगार रही है। इस सड़क की वजह से वाराणसी के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले लोगों के लिए एयरपोर्ट, लखनऊ, अजमगढ़ और गाजीपुर जाना काफी आसान हो गया है। जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो उन्होंने बच्चों, गृहिणियों और पुरुषों को अपने घरों के बाहर या अपनी छतों पर देखा। इसके बाद वहां मौजूद लोगों की ओर प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन



किया। इस दौरान लोगों ने हर-हर महादेव के नारे भी लगाए। एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे किसी ने अपने घर से रिकॉर्ड किया है। इसमें पीएम मोदी को लोगों का अभिवादन करते हुए गुजरते हुए देखा जा सकता है। वाराणसी पहुंचकर सड़क का निरीक्षण करते हुए जब पीएम मोदी ने अपनी तस्वीरें शेरार कीं, तो लोगों ने जमकर कमेंट किए। एक यूजर ने लिखा, देश की मिट्टी से बने, भारत माता के सुपुत्र की ऊर्जा तो देखो, पूरे दिन गुजरात में कार्यक्रम नौ बजे रात को समाप्त करके ग्यारह बजे रात को काशी में काम का निरीक्षण कर रहे हैं। धन्य है भारत ऐसा प्रधानमंत्री पाकर।

ताहिर असलम ने पाकिस्तान पर कसा तंज-

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का गठबंधन ड्रामा सिर्फ सेना को खुश करने के लिए



इंटरनेशनल डेस्क- एक पाकिस्तानी कनाडाई प्रसारक ने दावा किया है कि पाकिस्तान के दो प्रमुख राजनीतिक दलों पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के गठबंधन सरकार बनाने के समझौता सेना को खुश करने के लिए ड्रामा है। एक साक्षात्कार में पाकिस्तानी कनाडाई प्रसारक ताहिर असलम गौरा ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी पार्टी के लिए उपयुक्त नहीं और यह केवल पाकिस्तानी सेना की जरूरतों को पूरा करने का एक उपाय है। पाकिस्तान में चुनाव कराना पाकिस्तानी सेना के लिए एक वास्तविक संघर्ष था। उन्होंने कहा, सली संघर्ष तो पाकिस्तान की सेना का रहा है, उसे अपना एक प्रधानमंत्री चाहिए नहीं तो पीपीपी और पीएमएल-एन का गठबंधन इन दोनों पार्टियों को शोभा नहीं देता और ऐसी

सरकार उन्हें शोभा नहीं देती उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भयानक है, पाकिस्तान में आतंकवाद भयानक है। इस पूरी स्थिति में, यह उनमें से किसी को भी शोभा

नहीं देता। पाकिस्तानी कनाडाई प्रसारक ने कहा यहां तक कि पीपीआई नेता भी सरकार नहीं बनाना चाहते, क्योंकि वे जानते हैं कि तीन महीने बाद उन्हें इसका खामियाजा भुगतना

पड़ेगा। बहुत सारे बिल और लोग चिल्लाएंगे। ताहिर ने तेजी से विकास के लिए भारत की सराहना की जबकि पाकिस्तान कई मुद्दों से जूझ रहा है।यह दुखद है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसके पड़ोस में यह देश आतंकवाद, वित्तीय संकट से जूझ रहा है और अपने सहयोगियों को दर्द देने के बाद इस स्थिति में पहुंच गया है कि यह दिवालिया होने की कगार पर है और इसका लोकतंत्र दिवालियापन का सामना करना पड़ रहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान में नए गठबंधन से पड़ोसी भारत के साथ संबंधों में सुधार का कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा, ताहिर गौरा ने कहा, यह कोई नई सरकार नहीं होगी। यह पीडीएम 2.0 सरकार होगी। हर कोई चाहता है और भारत भी लेकिन सेना ऐसा नहीं होने देगी। सरकार तो सेना है

सेना ही देश चलाती रही है और आगे भी चलाती रहेगी। उन्होंने कहा, 76 साल से जो नफरत के बीज बोए गए हैं, वे रातोरात नहीं जाएंगे। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान के भारत के साथ अच्छे संबंध होंगे। पाकिस्तानी कनाडाई प्रसारक ने पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवाद के बढ़ने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में लगातार सरकारों द्वारा धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा दिया गया है। सांप हमेशा काटेगा। आपने जिस तालिबान का समर्थन किया है वह अब कह रहा है कि हम डूरे रेखा को नहीं पहचानते हैं। जिन आतंकवादियों को आपने कश्मीर में गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया है। अब आपके क्षेत्र में हमले कर रहे हैं। पाकिस्तानी समाज को निश्चित रूप से इन चुनौतियों का सामना करना होगा।